A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 26 जुलाई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 22, अंक 317, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से कौन ज्यादा फायदे में?

प्रवीण

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने छह अरब पाउंड की फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ब्रिटेन की कार और व्हिस्की भारत में सस्ती होंगी। वहीं भारत के कपड़े और गहने ब्रिटेन में सस्ते होंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों ही इस ट्रेड डील से फायदा होने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस डील से किसे ज्यादा फायदा होगा?

पीएम मोदी ने ने कहा है कि इस डील की मदद से भारतीय कपड़ों, जूते-चप्पल, आभूषण, सी फूड और इंजीनियरिंग से जुड़ी वस्तुओं को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इस डील के कारण भारतीयों की ब्रिटेन में बने उत्पादों तक पहुंच बढ़ेगी और वे मेडिकल डिवाइस और एयरोस्पेस पार्ट्स को किफायती दामों पर हासिल कर पाएंगे। वहीं पीएम स्टार्मर ने डील को ब्रिटेन के लिए जीत बताया है। इस डील से ब्रिटेन में 2200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, जलवायु और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है।

लेकिन इस डील को अभी ब्रिटेन की संसद की मंजूरी मिलना बाकी है और इसके प्रभावी होने में कम से कम एक साल का वक्त लग सकता है। भारत-ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील में तीन साल का वक्त लगा है। दिल्ली-स्थित थिंकटैंक, रिसर्च एंड इन्फ़र्मेशन सिस्टम फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज़ (आरआईएस) के महानिदेशक बिस्वजीत धर का मानना है कि बाकी विकसित देशों के मुकाबले भारत, ब्रिटेन के साथ काफी जल्दी इस डील को साइन करने में कामयाब रहा है। भारत में काफी छोटे किसान और व्यापारी हैं, वो इस तरह की ट्रेड से असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार को उन्हें समझाने और मनाने में काफी वक्त लगता है। इसलिए भारत को दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील करने में ज्यादा वक्त लगता है। फिर भी ये ट्रेड डील काफी कम वक्त में हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ हम 18 साल से ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े देशों के साथ ट्रेड डील करने में हमें काफी समय लग रहा है।

हालांकि समझौते के मुताबिक भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ कम होगा। इनमें कपड़े और जूते शामिल हैं। इस डील से भारत से ब्रिटेन में निर्यात होने वाले खाने और फ्रोजन प्रॉन्स पर लगने वाले टैरिफ में भी कटौती होगी। इसके अलावा कारों के निर्यात पर भी टैरिफ कम लगेगा। भारत के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच मिलने की भी उम्मीद है।

ब्रिटेन भारत से करीब 11 अरब पाउंड (करीब 1285 अरब रुपये) का सामान आयात करता है। टैरिफ कम होने की वजह ब्रिटेन में भारतीय निर्यात सस्ता हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक ट्रेड डील से ब्रिटेन का भारत से आयात बढ़ सकता है।

आईसीआरए लिमिटेड की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के मुताबिक बीते एक दशक में ब्रिटेन के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस मामूली रूप से बढ़ा है। एफटीए से कपड़ा, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स से जुड़े सामान और चमड़े समेत विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। 'टैरिफ के कम होने की वजह से भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। मेटल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, अल्कोहलिक पेय पर्दाथों और कॉस्मेटिक क्षेत्रों से जुड़े भारतीयों को भी इससे फायदा मिलेगा।' फ्री ट्रेड डील से ब्रिटेन में भारत से सोने-हीरे के आभूषण, कपड़ों और चमड़े के सामान के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

ब्रिटेन बासमती चावल, झींगा, मसालों और चाय पर आयात शुल्क में भी कटौती करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों की ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। बिस्वजीत धर कहते हैं कि भारत इस ट्रेड डील से काफी फायदे की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा, 'ब्रिटेन ने भारत के साथ निर्यात को लगभग खत्म ही कर दिया है। खिलौने और कपड़े से जुड़े क्षेत्रों में भारत को निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।'

'हालांकि अर्थशास्त्री शरद कोहली का मानना है कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इस डील से भारत को कितना फायदा होगा। क्योंकि ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। क्योंकि उनके पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं है।'

पीएम मोदी ने इस डील से दोनों देशों के सर्विस सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, 'इस डील से दोनों देशों के सर्विस सेक्टर को फायदा होगा। खासकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के सेक्टर में। इससे व्यापार में आसानी होगी और व्यापार करने की लागत भी कम होगी। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।' वहीं बिस्वजीत धर कहते हैं, 'भारतीय श्रमिकों को तीन सालों के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतानों से छूट मिलने से उनका खर्चा कम होगा। इससे वहां जाने वाले या वहां रहने वाले भारतीयों को फायदा हो सकता है।'

ब्रिटिश सरकार उम्मीद कर रही है कि कई सालों के बाद हुई डील से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को 4.8 अरब पाउंड यानी करीब 560 अरब रुपये का फायदा हो सकता है। ब्रिटेन से आयात पर भारत में औसतन 15 फीसदी टैरिफ लगता था जो इस डील के बाद घटकर तीन फीसदी रह जाएगा। टैरिफ कम होने की वजह से ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। बिस्वजीत धर कहते हैं, 'अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन, भारत से पीछे हो गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो उसे बड़े मार्केट की तलाश है। चीन को छोड़कर इंडिया जैसा बड़ा मार्केट कहीं और है नहीं। सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन के ऑटोमोबाइल सेक्टर को होगा।'

शरद कोहली का मानना है कि 'ट्रंप के ट्रेड वॉर छेड़ने की वजह से दुनिया में अर्थव्यवस्था उथल-पुथल हो गई है। लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि बाकी देश अपनी डील को जल्दी पूरा कर रहे हैं। इस ट्रेड डील के भारत और चीन के व्यापार संबंध पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन को ब्रिटेन के साथ व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

स्कूल की बिल्डिंग गिरने से आठ बच्चों की मौत

● राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा, 27 से ज्यादा घायल

छात्रा बोली- पहले कंकड़ गिरे लेकिन टीचर ने ध्यान नहीं दिया

झालावाड़ (एजेंसी)। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर हैं। मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए थे। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मनोहरथाना हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी, वहीं 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। गांववालों ने बताया कि वहां सुबह से बारिश हो रही थी। प्रार्थना का समय हुआ तो सभी क्लास के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने की बजाय कमरे में बैठा दिया, ताकि वे भीगे नहीं। इसके कुछ देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। गांववालों ने बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम है। हादसे के दौरान स्कूल के क्लासरूम में 71 बच्चे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन छत गिरने के वक्त बिल्डिंग से बाहर थे, वे सुरक्षित हैं। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने बताया की छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे,लेकिन टीचर्स ने नहीं देखा।

भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपए का दिया कर्ज

● फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई बातचीत, दोनों देशों के संबंधों पर डाक टिकट जारी

दो दिन के दौरे पर पीएम मोदी, स्वतंत्रता समारोह में होंगे मुख्य अतिथि

माले (एजेंसी)। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। यहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट (कर्ज) दिया की और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात की। दोनों देशों के डिप्लोमैटिक संबंधों के 60 साल पूरे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं को शुरू किया गया। भारतीय पीएम की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। वे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के न्योते पर मालदीव गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर मालदीव पहुंच गए हैं। उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया।

गुना जिले में 175.76 करोड़ लागत से 604 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि-पूजन

पीकेसी के साथ कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना से गुना जिले के खेत होंगे सिंचित : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। हमारे यहां कोई ग्लेशियर नहीं हैं, लेकिन सघन वन और जलराशि उपलब्ध है। प्रदेश का कोई भी गांव, कोई भी खेत पानी से वंचित न रहे इसके लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में तीन बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना इन्हीं में से एक है। गुना जिले को पीकेसी के साथ-साथ कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना का भी बड़ा लाभ मिलेगा इससे यहां के गांव-गांव और खेत-खेत तक पानी पहुंचेगा। यह परियोजना गुना जिले की तस्वीर बदल देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीनागंज में पीकेसी नदी लिंक परियोजना के लिए जिलेवासियों द्वारा आयोजित आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने करीब 5138 करोड़ रूपए की लागत वाली कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से गुना जिले की 30 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को बारहमासी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना जिले के समग्र विकास के लिए कुल 175.76 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न श्रेणी के 604 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को गुना जिले के बीनागंज में बहनों ने लाडले भाई मुख्यमंत्री डॉ यादव को स्नेह पूर्वक बड़ी राखी बांधी । मुख्यमंत्री का बीनागंज आगमन पर नागरिकों ने आत्मीय अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंच से ग्राम बीनागंज के श्री राजेश खंडेलवाल की बेटी के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। बेटी के इलाज के लिए सरकार द्वारा एक लाख रूपए पहले ही दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती ममता विश्वकर्मा को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बीनागंज में गौशाला के संपूर्ण विकास के लिए 12 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्या पूजन एवं दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का विधिवत् शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भगवान गणेश की गोबर से निर्मित प्रतिमा भेंटकर स्वागत किया गया। क्षेत्रीय बहनों ने श्रावण मास पर मुख्यमंत्री को दो बड़ी राखियां भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंच से लाड़ली लक्ष्मी योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं के चिन्हित हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चाचौड़ा के दर्शनीय स्थलों पर केंद्रित एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 2003 तक विपक्षी दल की सरकार थी और उस दौर में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिला।

लाड़ली बहनें अगर फैक्ट्री में काम करेंगी 14 हजार रुपए मेहनताना दिलवाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिल चुका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के पास अपना कोई मकान नहीं, लेकिन वे करोड़ों लोगों के मकान बनवा रहे हैं। गरीब-जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत के अलावा निःशुल्क राशन योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, बहनों को 250 रुपए का शगुन मिलेगा। प्रदेश की लाड़ली बहनों को इसी साल दीपावली से 1500 रुपए हर माह भेजे जाएंगे। लाड़ली बहनें अगर फैक्ट्री में काम करेंगी, तो उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 14 हजार रुपए मेहनताना दिलवाएंगे। युवाओं को भी रोजगार के लिए फैक्ट्री में काम करने पर सरकार 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हम केन्द्र सरकार के साथ मिलकर पात्र किसानों को कुल 12 हजार रुपए दे रहे हैं, जिसमें 6 हजार रूपये केन्द्र से एवं 6 हजार राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश में सोलर पॉवर से चलित सिंचाई पंप बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार विरासतों का हरसंभव तरीके से संरक्षण करते हुए प्रदेश को विकास की धारा से जोड़ रही है।

सुप्रभात

मेरी भाषा
कक्षा में पढ़ाई जाने वाली कोई भाषा नहीं थी
वो न तो हिंदी थी
न अंग्रेज़ी
न संस्कृत की तरह अभिजात
न उर्दू जितनी चाशनी लिपटी हुई
वो भाषा थी मेरी माँ के झुँझलाने की
पानी गिरा हो और उसने कहा हो कि
'ध्यान कहाँ है तेरा?'
वो भाषा थी पिता की खामोशी की
जिसमें तंबाकू की गंध
और थकान की चुप्पी लिपटी रहती थी
मेरी भाषा वह थी
जिसमें दादी ने पहली बार मुझे डाँटा था
'तू फिर खेल में लगी है!'
और फिर उसी में
थाली खिसका कर चुपचाप खाना परोस दिया था
जिसमें मेरी बहन ने पहला झूठ बोला
'ठीक हूँ'
और फिर बहुत देर तक रोती रही
मेरी भाषा की कोई लिपि नहीं थी
वो आँखों की कोर से फिसलती रही
रसोई के चूल्हे से उठती रही
छत पर सूखते कपड़ों के बीच फड़फड़ाती रही
जब मैंने किताबों में भाषा पढ़ी
तो जाना
मेरी भाषा को अपशब्द कहते हैं
मेरे मुहावरे अशिष्ट हैं
मेरी बोली गँवारू है
तब मैं चुप हो गई
शब्दों को रुई की तरह दबाकर रखने लगी
कि कहीं कोई सुन न ले
मेरी असल भाषा
लेकिन जब मैंने पहली बार प्यार किया
तो वो भी मेरी भाषा में हुआ
जिसमें 'हाँ' कहना
'जा' कहने जितना तीखा था
और 'रुक' कहना
मिट्टी जैसी कोमलता लिए होता था
अब मैं अपनी भाषा में लिखती हूँ
बिना किसी व्याकरण
बिना किसी अनुवाद के
जिसे जो समझना है समझे
मेरी भाषा
मेरे जैसी है
थोड़ी टूटी
थोड़ी रूखी
पर पूरी तरह सच्ची।

- मालिनी गौतम

भारत ने ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट, सटीक रहा निशाना

● टैंक-बंकर और ऊंचे इलाकों में दुश्मन को करेगी तबाह ● लॉन्चिंग के बाद टारगेट अपडेट भी कर पाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली लक्ष्यभेदी मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी 3 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के कर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में किया गया। इस रेंज को नोअर भी कहा जाता है। यह मिसाइल आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों को न्यूनतम जोखिम के साथ नष्ट करने की क्षमता शामिल है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपनी गति, सटीकता और लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर डीआरडीओ और इसके पार्टनर्स को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, उनके उद्योगिक साझेदारों, डेवलपमेंट कंपीटेंट प्रोडक्शन पार्टनर्स, एमएसएमईएस और स्टार्टअप्स को बधाई। यह सफलता दर्शाती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को आत्मसात करने और उत्पादन करने में सक्षम है। वी-3 का यह वर्जन पूर्ववर्ती वी 2 वेरिएंट का एडवांस रूप है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35°c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 26 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

देश को चौबीस घंटे और 365 दिन सैन्य तैयारी रखनी होगी

- सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान युद्ध में कोई उपविजेता नहीं
- कहा- ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है, जो अभी भी जारी है

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और देश की सैन्य तैयारी चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष बहुत उच्च स्तर पर बनी रहनी चाहिए। राजधानी दिल्ली के सुब्रतो पार्क में आयोजित एक रक्षा संगोष्ठी में अपने संबोधन में, उन्होंने यह भी कहा कि (पीओके) में कई आतंकी ढांचों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले किए और उसके बाद भारत द्वारा किए गए सभी जवाबी हमले भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही किए गए। 10 मई की शाम को एक समझौते पर पहुंचने के बाद दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच सैन्य संघर्ष रुक गया। सीडीएस ने

भविष्य में सेना को सूचना योद्धाओं, प्रौद्योगिकी योद्धाओं और विद्वान योद्धाओं की भी जरूरत होगी। सीडीएस ने कहा, और युद्ध के इस बदलते परिदृश्य में भविष्य के सैनिक को सूचना, तकनीक और विद्वान योद्धाओं तीनों का मिश्रण होना आवश्यक होगा। सीडीएस ने कहा कि युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता है, और किसी भी सेना को लगातार सतर्क रहना चाहिए और उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखनी चाहिए। जनरल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है, जो अभी भी जारी है। हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, चौबीसों घंटे, पूरे साल। भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर शास्त्र (युद्ध) और शास्त्र (ज्ञान प्रणाली) दोनों के बारे में सीखने के महत्व पर भी जोर दिया। सीडीएस ने जोर देकर कहा कि भविष्य के युद्ध में न केवल पारंपरिक युद्ध भूमिकाओं में बल्कि तकनीकी, सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी कुशल व्यक्तियों का वर्चस्व होगा। उन्होंने कहा, आधुनिक योद्धाओं को बहु-क्षेत्रीय अभियानों में निपुण होना चाहिए, और एक साथ तकनीकी योद्धा, सूचना योद्धा और विद्वान योद्धा के रूप में कार्य करना चाहिए। चौहान ने समकालीन सैन्य अभियानों में विद्वानों की बढ़ती जटिल भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया और बताया कि आज का परिदृश्य सैन्य विद्वानों की टीमों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की मांग करता है।

भारी बारिश से पानी-पानी हो गई मुंबई नगरिया

- सड़कों और गलियों से लेकर घरों तक में भर गया पानी
- प.बंगाल में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश जारी है। इसके चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से जरूरत न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी है। समुद्र तटीय इलाकों में जाने से बचने को भी कहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान जिले में गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं, ओडिशा पुलिस ने गंधमर्दन पहाड़ियों पर फंसे 17 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क धंसने से एक बस हादसे का शिकार

हो गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक कुल 147 मौतें हो चुकी हैं। वहीं, 1387 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी,बंगाल और ओडिशा के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

राबड़ी ने सम्राट को बताया गुंडा कहा-लड़कियों को छेड़ते हैं

- विपक्ष के काले कपड़े को देख भड़के नीतिशे

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन लंच के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही 7 मिनट के बाद स्थगित कर दी गई। ढाई बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। स्पीकर ने अपनी क्लोजिंग स्पीच में 3 शायरियां पढ़ीं। उन्होंने कहा- नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना आंखों को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। खूबियां तो

इतनी नहीं हममें कि तुम्हें कभी याद आएंगे पर इतना तो इतबार हमें खुद पर है आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। पहले सेशन में राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर कहा कि वो बचपन से बोरिंग रोड इलाके में गुंडई करता है। बोरिंग रोड चौराहे पर लड़कियों को छेड़ते रहे। वो कैसे दूसरे को गुंडा बोल सकते हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में तेजस्वी से कहा था- जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा।

हम ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाए: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने मानी अपनी गलती, कर दिया बड़ा वादा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह ओबीसी हितों की उतनी रक्षा नहीं कर पाए, जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। राजधानी दिल्ली में आयोजित 'भागीदारी न्याय महासम्मेलन' में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जातिगत जनगणना ना करवा पाना मेरी गलती है। मैं अब इसे सुधारना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, मेरा उद्देश्य देश की उत्पादक शक्ति को सम्मान दिलाना है। ओबीसी, दलित, आदिवासी देश की उत्पादक शक्ति हैं, लेकिन उन्हें अपने श्रम का फल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने जानबूझकर ओबीसी का इतिहास मिटाने की कोशिश की है।

देशभक्ति दिखाएं, गाजा की बजाय यहां ध्यान दें

वामपंथी दल को मुंबई हाईकोर्ट ने दी मुफ्त की नसीहत

मुंबई (एजेंसी)। गाजा में इजरायल की ओर से किए जा रहे कथित नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति के लिए वामपंथी दल सीपीएम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पार्टी को अदालत ने प्रदर्शन की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन यह नसीहत जरूर दी कि हजारों मील दूर के किसी मसले की बजाय भारत के किसी मुद्दे पर ध्यान दे। सीपीएम की मांग थी कि उसे आजाद मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, जिससे मुंबई पुलिस ने इनकार कर दिया है। जस्टिस रविंद्र घुगे और गौतम अखंड की बेंच ने अर्जी को

खारिज करते हुए कहा कि आपको हजारों मील दूर के किसी मसले की बजाय ऐसे मसलों पर ध्यान देना चाहिए, जिनका भारत पर असर होता हो।

देश में जहर बांट रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग : मल्लिकार्जुन

- मल्लिकार्जुन खरगे का हमला, कहा-नरेंद्र मोदी हैं झूठों के सरदार
- प्रधानमंत्री पर तीखा वार, बीजेपी-आरएसएस पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली के तालकटोरा

स्टेडियम में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। झूठ बोलना ही उनका काम है। उन्होंने देश से झूठ बोला कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, विदेश से कालाधन लाऊंगा। सबको 15-15 लाख दूंगा। किसानों को फायदा दूंगा। बैकवर्ड क्लास की आमदनी बढ़ा दूंगा। नरेंद्र मोदी संसद तक में झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि आरएसएस-बीजेपी के लोग जहर बांटते हैं। ये लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमें एकजुट रहना है। हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। जिस तरह से आजादी के समय लोगों ने साथ दिया था, वैसे ही आप लोगों को हमारा साथ देना है।

उपराष्ट्रपति चुनाव

इस्तीफा देकर भी 'मुसीबत' खड़ी कर गए हैं धनखड़!

- बीजेपी के सामने दो चुनौतियां पार करना होगा टेढ़ी खीर

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन में भी इस पद को लेकर सलाह मशविरा शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा देकर भी वह बीजेपी के लिए दो चुनौतियां छोड़ गए हैं। पहली चुनौती तो यह है कि इस बार उम्मीदवार का चयन करने में बीजेपी को सतर्क रहना होगा। बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहेगी जिसकी विचारधारा पार्टी से एकदम मेल खाती हो। दूसरी चुनौती यह है कि विपक्ष भी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। दोनों सदनों को मिलाकर इस चुनाव में 782 सांसदों का इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इसमें एनडीए के 425 सांसद हैं। जगदीप धनखड़ ने अपना राजनीतिक सफर 1991 में जनता दल के सांसद के तौर पर शुरू किया था। बाद में उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली और फिर बीजेपी में आ गए। जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट

में एक सीनियर वकील थे। ऐसे में बीजेपी का उनपर ध्यान गया और उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। राज्यपाल रहते हुए उनकी ममता बनर्जी सरकार के साथ ठनी ही रहती थी। 2022 में जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया।

प्रदर्शनकारी बोले-बिजली महादेव रोप-वे मंजूर नहीं

हिमाचल में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध

कुल्लू (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बिजली महादेव रोप-वे का हिमाचल में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कुल्लू आज सैकड़ों लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। मंडी के सेरी मंच पर भी लोगों ने रोष रैली निकालकर इस प्रोजेक्ट का विरोध जताया। वहीं कुल्लू के रामशीला में एकत्र हुए लोगों ने ढालपुर मैदान तक आक्रोश रैली निकाली। अब ढालपुर मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल्लू का ढालपुर ग्राउंड पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील है। सांसद कंगना

रनोट भी कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट का विरोध कर चुकी हैं। तब कंगना ने कहा था कि कि यदि देव समाज के लोग नहीं चाहते तो यह प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी के करीबी राम सिंह समेत कई भाजपा नेता भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। बिजली महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष विरोध में हैं।

कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा केंद्र

सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई जजों की नियुक्ति भी अटकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मुद्दा प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने इस मामले को उठाते हुए बताया कि कुछ जजों के नाम 2019 से केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा, ये नाम चार साल से लंबित हैं, जिसके कारण उम्मीदवारों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। दातार ने जोर देकर कहा कि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों को तीन-चार साल तक लंबित नहीं रखना चाहिए और समय-सीमा का पालन करना आवश्यक है। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

आरओ और एआरओ का ऐलान तैयारियां भी हो गई तेज

- उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ऐक्टिव हुआ चुनाव आयोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही होने की संभावना है। चुनाव में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए समय लगेगा। चुनाव आयोग संसद के दोनों सदनों की मतदाता सूची की जांच कर रहा है। राज्यसभा के महासचिव चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद चुनाव प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी करनी होगी। नियमों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 14 दिन, फिर जांच के लिए तीन-चार दिन और प्रचार के लिए 14 दिन मिलेंगे। इसलिए, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही होगा। मानसून सत्र 21 अगस्त को खत्म हो रहा है और इसमें सिर्फ 20 दिन बचे हैं। संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में फिलहाल 782 सदस्य हैं।

1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर थाईलैंड-कंबोडिया में जंग

अब तक 16 की मौत, थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों से 1 लाख लोगों को हटाया

बैंकॉक/नोम पेन्ह (एजेंसी)। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 हजार साल पुराने दो शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार सुबह दोनों देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर फायरिंग की। थाई सरकार ने आज बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब तक थाईलैंड के 15 लोगों की मौत हुई है। इसमें 1 सैनिक और 14 आम लोग हैं। 46 लोग घायल हुए हैं। अभी तक कंबोडिया की तरफ से मृतकों या घायलों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में 1 शख्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया का इतिहास लंबे समय तक खमेर साम्राज्य (कंबोडिया) और सियाम साम्राज्य (थाईलैंड) के बीच टकरावों से जुड़ा रहा है। फ्रांस और ब्रिटिश शासन के दौरान भी दोनों देशों की सीमाओं को तनाव था, जिसकी वजह से प्रीह विहियर (प्रिय विहार) और ता मुएन थॉम मंदिरों के आसपास की जमीन पर अधिकार को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद लगातार चलता रहा था। 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था तब दोनों देशों के बीच 817 किमी की लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका

विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्रीह विहियर (प्रिय विहार) मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। वहीं, ता मुएन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इसे अपना मानता है। प्रीह विहियर मंदिर पर थाईलैंड का दावा प्रीह विहियर मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज्यादा है। थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार लगा रहा, जिसके बाद 1959 में कंबोडिया यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया। साल 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने का आदेश दिया। तब थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रखा। 2008 में यह विवाद तब बढ़ा जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को में शामिल कराने की बात की।

आर्थिक अनियमितता के कारण लेखापाल को नौकरी से हटाया

भोपाल (नप्र)। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लेखापाल ज्ञानेन्द्र शर्मा को वित्तीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप के कारण पद से हटा दिया गया है। विभागीय जाँच में यह तथ्य सामने आया है कि ज्ञानेन्द्र शर्मा ने लेखापाल के पद पर रहते हुए बिना सक्षम स्वीकृति और बिना अधिकृत भुगतान आदेश के डीडीओ की लॉगइन आईडी का दुरूपयोग कर भुगतान की कार्यवाही की थी। जांच में यह संपूर्ण प्रक्रिया वित्तीय नियमों के प्रतिकूल और धोखाधड़ी की श्रेणी में आती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने लेखापाल ज्ञानेन्द्र शर्मा को पद से हटाने संबंधी आदेश जारी किये हैं। आयुक्त ने कहा है कि लेखा संबंधी कार्यों में यदि किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही की जाती है तो विभाग द्वारा उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और इसी प्रकार की कार्रवाई की जायेगी।

मवेशी से टकराकर युवक की मौत

ईटखेड़ी इलाके की घटना, पुलिस ने शुरू की जांच

भोपाल (नप्र)। भोपाल में बाइक सवार सड़क पर बैठे मवेशी से टकराकर घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ईटखेड़ी थाना पुलिस ने बताया कि ग्राम रोड़िया गुनगा निवासी नर्मदा प्रसाद पुत्र गोपीलाल (40) मेहनत-मजदूरी करते हैं। गत 16 जुलाई की रात वह किसी काम के सिलसिले में बाइक लेकर निकला था। जब वह निपानिया जाट के पास मेन रोड से गुजर रहा था। तभी उसकी बाइक बीच सड़क पर बैठे मवेशी से टकरा गई, जिससे बाइक समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गया था।

नौ दिन चले इलाज के बाद मौत– हादसे के बाद घायल युवक को उसके परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां पर हालत में सुधार न होने पर उसी रात एम्स रेफर किया गया था। यहां पर नौ दिन तक चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की दोपहर को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

चुनाव आयोग ने बीएलओ का मानदेय किया दोगुना

अब एक साल में 12 हजार रुपए मिलेंगे, स्पेशल ड्राइव का इंसेंटिव अलग से मिलेगा

भोपाल (नप्र)। बिहार चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) की प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। एमपी में काम करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाली यह मानदेय राशि अब दोगुनी हो गई है। अभी तक इन्हें छह हजार रुपए मिला करते थे और अब आयोग के फैसले के बाद 12 हजार रुपए मिलेंगे।

चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को इसके आदेश जारी कर देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसके आधार पर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अफसरों के अनुसार चुनाव आयोग का मानदेय बढ़ाने संबंधी आदेश एमपी को भी मिला है और इसके लिए नोटशीट जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर बूथ लेवल अफसर और सुपरवाइजर को बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि देश के अलग-अलग राज्यों में बीएलओ को अलग-अलग मानदेय दिया जाता है। एमपी में कम राशि मिल रही थी। अब नए निर्देश के बाद इन्हें हर महीने एक हजार रुपए के हिसाब से मानदेय मिलने लगेगा। पहले यह 500 रुपए महीने के हिसाब से मिल रहा था।

अब ऐसे मिलेगा बीएलओ, सुपरवाइजर को मानदेय

- बीएलओ को अभी तक एमपी में 6 हजार रुपए मिलते थे और चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब 12 हजार रुपए सालभर में मिलेंगे।
- सुपरवाइजर को अभी तक 12 हजार रुपए मिलते थे और अब नए निर्देश के बाद इन्हें सालभर में 18 हजार रुपए मिलेंगे।
- चुनाव आयोग ने इसके साथ ही चुनाव कार्य करने वाले बीएलओ को स्पेशल ड्राइव चलाने पर 2000 रुपए इंसेंटिव देने का भी फैसला किया है।

राज्यपाल पटेल ने दिव्यांग बालिकाओं के साथ किया सह-भोज

राज्यपाल का सांकेतिक भाषा में बहुदिव्यांग बालिकाओं ने जताया आभार

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जीवन में सफलता और आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखते रहना चाहिए। राज्यपाल बहुदिव्यांग बालिकाओं से उनके शिक्षकों के माध्यम से राजभवन के सभा कक्ष जवाहर खण्ड में आत्मीय चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल से सौजन्य भेंट करने के लिए आनंद सर्विस सोसायटी की मूकबधिर बहुदिव्यांग बालिकाएं शुक्रवार को इंदौर से राजभवन आई थीं। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता भी मौजूद थे।

निरंतर सीखने और आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित– राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने दिव्यांग बालिकाओं से उनके मार्ग दर्शकों के माध्यम से परिचय प्राप्त किया। उनके जीवन की कठिनाईयों और सफलताओं को जाना। उनको निरंतर सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दिव्यांग बालिकाओं के साथ बालिका सुश्री गुरदीप कौर वासु के संघर्ष और सफलता की कहानी पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने दिव्यांग बालिकाओं और शिक्षकों के साथ सह-भोज भी किया।

राजभवन भ्रमण के अनुभव किए साझा– राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने सभी बालिकाओं से राजभवन भ्रमण के अनुभव जाने और सामूहिक चित्र भी खिंचवाया। बालिकाओं ने सांकेतिक भाषा में ऐतिहासिक राजभवन परिसर और विशेष रूप से आर्ट गैलेरी भ्रमण के सुखद अनुभव साझा किए। उन्होंने राज्यपाल के प्रति मुलाकात, सह-भोज करने और राजभवन भ्रमण का अवसर देने के लिए आत्मीय आभार जताया।

राज्यपाल को स्व-रचित कलाकृतियां की भेंट

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से भेंट के अवसर पर मूकबधिर बहुदिव्यांग बालिका सुश्री दिव्या गोले और वैष्णवी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। उन्हें सुश्री किरण विश्वकर्मा और अन्य बालिकाओं ने स्वयं द्वारा सृजित पैंटिंग और कलाकृतियां भेंट की।

राज्यपाल ने देखी बहुदिव्यांग गुरदीप पर बनी फिल्म

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने बालिकाओं के साथ मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत मूकबधिर बहुदिव्यांग शासकीय सेवक सुश्री गुरदीप के जीवन और संघर्षों पर आधारित लघु फिल्म को देखा। उन्होंने उपस्थित बालिकाओं से गुरदीप के जीवन के संघर्षों और सफलताओं से प्रेरणा लेने और निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुरदीप के परिजनों, संस्था के शिक्षकों और प्रतिनिधियों के समर्पण की प्रशंसा की।

इस अवसर पर राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, संस्था की को-फाउंडर और संचालक श्रीमती मोनिका पुरोहित, सचिव श्री ज्ञानेन्द्र पुरोहित, गुरदीप की माताजी श्रीमती सीमा मंजीत कौर, शिक्षिका श्रीमती मृणालिनी शर्मा और बालिकाएं उपस्थित रही।

सहारा जमीन घोटाले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

भोपाल, जबलपुर और कटनी में बेची थी जमीनें, शिकायत की जांच के बाद लिया एक्शन

भोपाल (नप्र)। सहारा जमीन घोटाले में शुक्रवार शाम को शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है।

1000 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 98 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। जमीन बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का भी पालन नहीं किया गया। भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की जमीन को बेचा गया था। ईओडब्ल्यू ने यह बताया- सहारा की ओर से जमीनों को बेचकर कुल 72.82 करोड़ रुपए का गबन किया है। जबलपुर और कटनी की भूमि बिक्री के निर्णयों में कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रमुख सीमांतो रॉय सीधे तौर पर शामिल पाए गए। डीएमडब्ल्यू भोपाल के डीजीएम जेबी रॉय की भूमि सौदे के वित्तीय लेन-देन और निर्णयों में सक्रिय भूमिका थी। सागर भूमि सौदे के निर्णयों में सहारा के लैंड डिवीजन के प्रमुख होने के नाते डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव शामिल पाए गए।

इन दो तरीकों से आरोपियों ने की धोखाधड़ी– भोपाल और सागर में बिक्री की पूरी राशि 62.52 करोड़ को सेबी सहारा खाते में जमा नहीं किया गया।

जबलपुर, कटनी और ग्वालियर में अवैध कटौतियों के माध्यम से 10.29 करोड़ की हेराफेरी की गई।

जमीन बेचने के बाद निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया– सहारा की जमीन को बेचने के बाद भी सहारा में निवेश करने वालों को पैसा नहीं मिला था। ईओडब्ल्यू ने इन कंपनियों द्वारा सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने की पीई दर्ज कर की थी और इसी साल फरवरी महीने में जांच शुरू की थी। मामले में ईओडब्ल्यू ने क्रेता पक्ष और विक्रेता पक्ष के 9 लोगों से पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज की है।

सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी थी रकम– सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा कई शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से जमीनें खरीदी गई थीं।

साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कम्पनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जमीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा तक तय की गई थी।

प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि, पैसे खरीदार द्वारा सीधे मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के सेबी-सहारा रिफंड खाता नंबर 012210110003740 में जमा किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया विश्व में भारत का मान-सम्मान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज हमारे देश के लिए बेहद गर्व का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सेवा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय (4078 दिन) तक लगातार कार्यरत दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की महान लोकतांत्रिक परम्पराओं से ओत-प्रोत परिपक्वता, सुदीर्घ विकास यात्रा और जनविश्वास की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल देश के भीतर अभूतपूर्व परिवर्तन देखे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी खूबी से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं मध्यप्रदेश की सम्पूर्ण जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे दीर्घायु हों और इसी तरह देश का नेतृत्व करते हुए नये-नये कीर्तिमान स्थापित करते रहें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष न केवल सशक्त तरीके से रखा, बल्कि कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें आजादी के बाद देश के लोगों ने सर्वोच्च पद से सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित किया है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश और दुनिया के सामने भारत का मान-सम्मान बढ़ाने का अवसर दिया है। आज एक और नया रिकार्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ जुड़ा है, वे देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जो 4078 दिन तक न केवल प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि उनके कार्यकाल में भारत ने मान-सम्मान और कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत, आजादी के समय विश्व की 15वीं अर्थव्यवस्था था। जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यभार संभाला, तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मात्र 11 साल के अंदर ही भारत को चौथी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है और जब तक उनकी कार्यकाल अवधि पूर्ण होगी, तब तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश बना, जो देश के दुश्मनों को अपने यहां भी और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने में भी सक्षम हुआ है। पहले दुनिया के सिर्फ दो देश इजरायल और अमेरिका ही ऐसा काम कर पाते थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधामनंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्य करने का अपना तरीका है। उन्होंने देश को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा। भारत डिजिटल पैमेंट के मामले में दुनिया का अग्रण्य होने जा रहा है। दूसरे विकसित देशों में भी ऐसा नहीं होता है कि चाय वाले के यहां चाय पियो और डिजिटल पैमेंट कर दो। सब्जी, फल वाले सब्जी और फल खरीदो और डिजिटल पैमेंट कर दो। ऐसे कई नवाचार करते हुए गरीब वर्ग के लिए भी पूरे देश में श्री मोदी के नेतृत्व में एकमात्र सरकार है जो देश की 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देकर उनके खाने-पीने और रहने की चिंता दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के तहत 60 साल तक के गरीब व्यक्तियों का पांच लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज और 70 साल की आयु वाले सभी समाज/वर्गों के व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देकर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक नहीं अनेक प्रकार से भारत की जनता का मान-सम्मान बढ़ाया है।

उद्योग-व्यापार और वैश्विक संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा ब्रिटेन से मुक्त व्यापार समझौता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट-एफटीए की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवाओं के साथ-साथ समूचा भारत गौरवान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो करार किया है, यह न केवल उद्योग, व्यापार और रोजगार की दृष्टि से, बल्कि वैश्विक संबंधों की दृष्टि से भी भारत को नई ऊंचाईयों पर लेकर जाएगा। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों से वैश्विक स्तर पर मिला विस्तार देश की बढ़ती प्रतिष्ठा का अतुलनीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम सभी को एफटीए के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। मध्यप्रदेश को भी भविष्य में ब्रिटेन के साथ हुए इस मुक्त व्यापार समझौते का भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नये मुक्त व्यापार समझौते से मध्यप्रदेश को कृषि सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, सर्विस सेक्टर, एविएशन सेक्टर, लेदर इंडस्ट्री, प्लास्टिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सहित मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

नीट यूजी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिका खारिज

इंदौर (नप्र)। बिजली गुल होने से प्रभावित हुए नीट जी 2025 के अभ्यर्थियों द्वारा रि-एग्जाम की मांग वाली दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दीं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट के निष्कर्ष सही हैं और रि-एग्जाम के आदेश पारित करना न्यायालय के हाथ में नहीं है, क्योंकि यह एनटीए का विशेषाधिकार है।

कोर्ट ने आगे कहा कि इंदौर उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सहित सभी संभावित पहलुओं से जांच की है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने निर्देश दिया कि जो छात्र काउंसलिंग के लिए पात्र हैं, वे पंजीयन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। रि-एग्जाम के लिए 52 छात्रों ने इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। एडवोकेट मृदुल भटनागर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को ही बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पीड़ित स्टूडेंटस की ओर से उनके एडवोकेट ने तर्क रखे कि बिजली गुल होने के दौरान संबंधित परीक्षा केंद्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। एनटीए की ओर से सॉलिसिटर एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस परीक्षा में देशभर के लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अब काउंसलिंग का दौर है।

ऐसे में इन स्टूडेंट्स की रि-एग्जाम व्यावहारिक नहीं है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क के साथ पीड़ित स्टूडेंटस की याचिका को खारिज कर दिया कि काउंसलिंग के समय में दोबारा परीक्षा कराना मुश्किल है।

हाईकोर्ट के फैसले को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

नीट यूजी के एग्जाम के दौरान बिजली गुल होने के मामले में 14 जुलाई को एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 75 से ज्यादा प्रभावित स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दीं थी।

हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की रिट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट द्वारा एनटीए की रिट अपील मंजूर करने के बाद उसी दिन शाम को ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। इसके बाद शाम 6 बजे एनटीए ने उन 75 स्टूडेंट्स, जिनके रिजल्ट पर स्टे था, उसे घोषित कर दिया। इसकी सूचना हर स्टूडेंट को उनके मेल पर दी गई।

16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट उन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ, जो परीक्षा में शामिल हुए थे और कुछ केंद्रों में जिन्हें बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था।

23 जुलाई को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

वन बल प्रमुख के लिए हुई डीपीसी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दावेदारों के नाम पर चर्चा आदेश जल्द होंगे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख (हॉफ) के लिए गुरुवार को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में नए वन बल प्रमुख के लिए नाम फाइनल किया गया। इसके आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस मीटिंग में राजस्थान के बजाय छत्तीसगढ़ के वन बल प्रमुख शामिल हुए। विभाग में सबसे सीनियर वीएन अंबाड़े प्रबल दावेदार हैं।

वन विभाग के मुखिया को हॉफ (हेड ऑफ फॉरेस्ट) कहा जाता है। वर्तमान में हॉफ की जिम्मेदारी असीम श्रीवास्तव निभा रहे हैं, जो 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद एक अगस्त से नए हॉफ की पदस्थापना को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर पहले बुधवार को बैठक होना थी जिसमें नए वन बल प्रमुख का नाम फाइनल कर आदेश जारी किया जाना था, लेकिन पदोन्नति कमेटी में शामिल राजस्थान के वन बल प्रमुख का स्वास्थ्य खराब होने और उनके अस्पताल में एडमिट होने की सूचना के बाद डीपीसी टल गई। इसके बाद गुरुवार को इसको लेकर बैठक हुई है।

छत्तीसगढ़ के हॉफ हुए बैठक में शामिल

राजस्थान के हॉफ के स्थान पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के हॉफ श्रीनिवासन को एमपी के हॉफ सिलेक्शन संबंधी बैठक में शामिल होने भेजा। इस मीटिंग में हॉफ के लिए विभाग के सबसे सीनियर अफसर वीएन अंबाड़े के नाम पर मुहर लग सकती है क्योंकि पिछले कई सालों में विभाग में सबसे सीनियर अफसर को ही इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अंबाड़े वर्तमान में वन विकास निगम में पीसीसीएफ हैं। बताया जाता है कि डीपीसी मीटिंग में वीएन अंबाड़े के अलावा दो अन्य अधिकारियों 1989 बैच के एचयू खान और 1990 बैच के विभाष ठाकुर के नाम भी चर्चा के लिए पैनल में रखे गए थे।

एम्स भोपाल की 3डी प्रिंटिंग लैब से चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा

भोपाल। कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देते हुए निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2024 में स्थापित कम्प्यूटेशनल 3डी मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग लैब अब चिकित्सा, अभियांत्रिकी और डिजिटल डिजाइन के संगम पर विकसित होता हुआ एक उभरता राष्ट्रीय नवाचार केंद्र बन चुका है। यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर, हाई-परफॉर्मेंस वर्कस्टेशन्स और उन्नत मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है, जिसकी मदद से अत्यंत सटीक, यथार्थवादी और रोगी-विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं तैयार की जाती हैं। इन संरचनाओं का उपयोग न केवल पूर्व-शल्य योजना और सर्जिकल प्रशिक्षण में हो रहा है, बल्कि दुर्लभ रोग मामलों के संग्रह, रोगी परामर्श और मेडिकल छात्रों के शिक्षण में भी किया जा रहा है। इससे चिकित्सकीय निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार और अंतरविभागीय ज्ञानवर्धन को बल मिल रहा है। लैब की एक प्रमुख उपलब्धि नेशनल सिम्पोजियम ऑन 3डी प्रिंटिंग एंड मॉडलिंग इन हेल्थकेयर का सफल आयोजन रहा, जिसमें देश-विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया और इस क्षेत्र में सहयोग आधारित नवाचार की मजबूत नींव रखी गई। अब लैब जुलाई 2025 से दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिनमें से एक मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

ये पाठ्यक्रम सिमुलेशन, सेगमेंटेशन और डिजाइन वर्कफ्लो पर आधारित होंगे। इसके साथ ही, मेडिकल और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए, लैब अब कम्प्यूटेशनल बायोमैकेनिक्स, सर्जिकल सिमुलेशन, वर्चुअल एनाटॉमिकल मॉडलिंग और फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने जा रही है। इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, लैब अब भारत की पहली रोगी-विशिष्ट 3डी एनाटॉमी और पैथोलॉजी रिपॉजिटरी एवं मॉडल गैलरी की स्थापना की तैयारी कर रही है। यह गैलरी चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और जन-जागरूकता हेतु दुर्लभ और प्रतिनिधिक क्लीनिकल मॉडलों का एक राष्ट्रीय संग्रह होगी, जो आने वाले समय में शिक्षण, अभ्यास और संवाद का एक अनोखा प्लेटफॉर्म बनेगी। अपने प्रभाव को और व्यापक बनाने हेतु लैब अब विश्वविख्यात संस्थानों और अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। इन साझेदारियों के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान, सिमुलेशन प्लेटफ़ॉर्म का विकास, फैकल्टी एक्सचेंज और बायोइंजीनियरिंग व हेल्थकेयर शिक्षा में व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर कार्य किया जाएगा।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, एम्स भोपाल की कम्प्यूटेशनल 3डी मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग लैब हमारी व्यक्तिगत चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ट्रांसलेशनल रिसर्च के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह तकनीक और नैदानिक दृष्टिकोण के समन्वय से ऐसे नवाचारों को जन्म दे रही है, जो चिकित्सकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों - सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। भारत की पहली रोगी-विशिष्ट शारीरिक संरचना गैलरी की स्थापना चिकित्सा विज्ञान को आमजन के लिए सहज और सुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी।

संपादकीय

अब आसियान में चीन का खेला?

पूर्व एशिया के दो बौद्ध बहुल देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हजार साल पुराने एक शिवमंदिर की जमीन को लेकर जिस तरह सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया है, उसके पीछे असल में चीन का हाथ होने की आशंका है। यूं चीन के दोनों देशों से रिश्ते हैं, लेकिन वह कंबोडिया को खुला समर्थन दे रहा है। इस संघर्ष से क्षेत्र में चीन का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि वह न केवल कंबोडिया को हथियार सप्लाई कर रहा है बल्कि वहां की सरकार को भी समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ थाईलैंड का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा है। उसकी आबादी, क्षेत्रफल और सैन्य शक्ति कंबोडिया की तुलना में काफी अधिक है। ऐसे में युद्ध अगर लंबा खिंचा तो कंबोडिया का टिकना मुश्किल होगा। ऐसे में चीन की दखलंदाजी और बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल उसने दोनों देशों से संयम से काम लेने और शांति बनाए रखने के लिए कहा है। वैसे शिव मंदिर का यह विवाद सवा सौ साल पुराना है और इस बात का प्रमाण है कि औपनिवेशिक काल में जो गलतियां हुई हैं, उसे दुनिया के कई देश आज भी भुगत रहे हैं। भारत पाकिस्तान इसका बड़ा उदाहरण है। वही हाल थाईलैंड और कंबोडिया का भी है। कंबोडिया पर लंबे समय तक फ्रांसीसियों का राज रहा। हालांकि थाईलैंड कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। आज से हजार साल पहले कंबोडिया में हिंदू खमेर वंश का शासन था, जिसे वहां के लोग आज भी याद करते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। विवादित शिव मंदिर जिसे स्थानीय भाषा में प्रीह विहार मंदिर कहा जाता है, विवाद की जड़ है। इस विवाद की जड़ें सौ साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जब फ्रांसीसी कब्जे के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थीं। हालात 2008 में तब औपचारिक रूप से तनावपूर्ण हो गए, जब कंबोडिया ने एक विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पंजीकृत कराने की कोशिश की।

थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुईं, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुईं। तनाव मई में तब और बढ़ गया, जब एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। पिछले दो महीनों में दोनों पड़ोसी देशों ने एक-दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल-सब्जी जैसी चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी, साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। ताजा संघर्ष में 11 लोगों की मौत हो गई है और 14 घायल हो गए हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह सैन्य तनाव पूर्ण युद्ध में बदलेगा या नहीं। लेकिन तनाव घटे ऐसा नेतृत्व भी दोनों देशों के पास नहीं है। दोनों देशों में राजनीतिक अस्थिरता है। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। वहां के प्रधानमंत्री, पूर्व सत्ताधारी नेता के बेटे हैं और अभी तक उनकी खुद की कोई ठोस राजनीतिक पकड़ नहीं बनी है। जबकि थाईलैंड में एक अस्थिर गठबंधन सरकार है, जिसके पीछे ताक़तवर नेता ताकसिन शिनावात्रा हैं। वो भी विवादों में रहे हैं। इस मामले को सुलझाने की आस आसियान संगठन से है। देखना होगा कि क्या आसियान के अन्य सदस्य इस टकराव में दखल देते हैं और दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए मनाते हैं या नहीं। जबकि उसकी प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि पूर्व एशिया के इन दो देशों के बीच तनाव और ज्यादा न फैले। दूसरे, आसियान असफल रहा तो चीन का इस क्षेत्र में अपना खेल करना तय है।

मस्जिद में मुलाकात बनाम कांवड़ पर पुष्पवर्षा

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सांसदों की संसद भवन के पास मस्जिद में हुई एक मुलाकात की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति को और प्रखर बना रहे हैं। ये घटनाएं इशारा कर रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब पूरी ताकत के साथ शुरू हो चुकी है, और इसका थीम पहले से तय हो गया है 'हरा बनाम भगवा'। 23 जुलाई को संसद भवन के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव, मोहिबुल्ला नदवी, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और जिया उर रहमान बर्क के साथ बैठते हुए तस्वीरें सामने आईं। तस्वीरों में दो महिलाएं भी नजर आईं, जिनमें से एक को मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और दूसरी को कैराना सांसद इकरा हसन बताया गया। भाजपा ने तुरंत इस मुद्दे को तूल दिया।

उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से धार्मिक और सामाजिक रंगों में रंगती दिख रही है। यह कोई अचानक उभरा मुद्दा नहीं है, बल्कि सावन की सोंधी हवा में 'हरा' और 'भगवा' का टकराव पहले से कहीं अधिक तीखा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सांसदों की संसद भवन के पास मस्जिद में हुई एक मुलाकात की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति को और प्रखर बना रहे हैं। ये घटनाएं इशारा कर रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब पूरी ताकत के साथ शुरू हो चुकी है, और इसका थीम पहले से तय हो गया है 'हरा बनाम भगवा'। 23 जुलाई को संसद भवन के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव, मोहिबुल्ला नदवी, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और जिया उर रहमान बर्क के साथ बैठते हुए तस्वीरें सामने आईं। तस्वीरों में दो महिलाएं भी नजर आईं, जिनमें से एक को मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और दूसरी को कैराना सांसद इकरा हसन बताया गया। भाजपा ने तुरंत इस मुद्दे को तूल दिया। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने संसद के बगल स्थित एक धार्मिक स्थल को राजनीतिक बैठक के लिए प्रयोग किया, जो संविधान का उल्लंघन है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें 'नमाजवादी' कह दिया और तीखा तंज कसा। उनका कहना था कि किसी भी धार्मिक स्थल का राजनीतिक इस्तेमाल संविधान के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी बार-बार इसकी अनदेखी करती रही है।

इतना ही नहीं, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने डिंपल यादव के परिधान पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब मस्जिद में गई थीं तो उन्हें सिर ढंकना चाहिए था। इस बयान को सपा ने तूल देने की कोशिश बताया और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश करार दिया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आस्था का मतलब जोड़ना होता है, जबकि भाजपा समाज में दूरियां पैदा करना चाहती है। उन्होंने साफ किया कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक मुलाकात थी जिसमें मोहिबुल्ला नदवी की पत्नी भी मौजूद थीं।उधर, भाजपा ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मस्जिदें सिर्फ इबादत का स्थल हैं, उन्हें राजनीति का मंच नहीं बनाया जा सकता। वहीं कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर असहमति जताई और मोहिबुल्ला नदवी से इस्तीफे की मांग कर डाली। मस्जिद की राजनीति ने दोनों पक्षों को न सिर्फ आक्रामक बना दिया है, बल्कि अब

धार्मिक संगठनों की नाराजगी भी सपा के लिए एक नई चुनौती बन गई है।

इस विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को भव्य रूप देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हेलिकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की गई, जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए और विशेष पुलिस बंदोबस्त किए गए। मुख्यमंत्री ने मेरठ और मुजफ्फरनगर में हवाई निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कांवड़ियों पर फूल बरसाए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उनके हिंदुत्व एजेंडे का विस्तार है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे 'दिखावा' करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछले 11 सालों से केंद्र में और 9 साल से यूपी में सरकार चला रही है, लेकिन कांवड़ियों के लिए कोई स्थायी ढांचा नहीं बना सकी। उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर सपा सरकार कांवड़ियों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाएगी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अब भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती देने के लिए खुद मैदान में उतर आई है। कैराना की सांसद इकरा हसन कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचीं और शिवभक्तों को प्रसाद वितरित किया। उनका भगवा पटका पहनकर प्रसाद बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि देश की साझा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वे हर धर्म का सम्मान करती हैं।

इस धार्मिक और राजनीतिक खींचतान के बीच यूपी की राजनीति का 2027 मॉडल धीरे-धीरे आकार ले रहा है। सपा का 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला और भाजपा का 'हिंदुत्व + विकास' का एजेंडा आमने-सामने खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं तो भाजपा कांवड़ यात्रा को प्रशासनिक और धार्मिक दोनों स्तर पर भव्य बना रही है। इटावा में अखिलेश यादव ने केदारेश्वर महादेव मंदिर का उद्घाटन कर यह संकेत दिया है कि वे भी हिंदू आस्था के मैदान में कदम रख चुके हैं। वहीं भाजपा सरकार काशी, अयोध्या और मथुरा में कॉरिडोर निर्माण के जरिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा को झटका दिया। सपा ने 37 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 33 पर सिमट गई। अब अखिलेश यादव इस लय को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहते हैं। पीडीए समीकरण के तहत वह गैर-यादव पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दांव लगाते हुए हिंदुत्व और विकास का दोहरा कार्ड खेल रही है।

प्रदेश में भाजपा की राजनीति हमेशा हिंदुत्व केंद्रित रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले, चाहे वह ढाबों के नाम बदलना हो या कांवड़ यात्रा को सरकारी संरक्षण देना इन सबका मकसद हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखना है। वहीं समाजवादी पार्टी खुद को 'गंगा-जमुनी तहजीब' की पार्टी बताकर भाजपा की धर्म आधारित राजनीति का विकल्प बनाना चाहती है। यही वजह है कि एक तरफ डिंपल यादव मस्जिद में नजर आती हैं तो दूसरी ओर इकरा हसन भगवा पटका पहनकर कांवड़ियों की सेवा करती दिखती हैं।डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रसाद मौर्य और अमित मालवीय जैसे नेताओं ने अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश मस्जिद गए, लेकिन सफेद जालीदार टोपी लगाना भूल गए। भाजपा के इन बयानों से साफ होता है कि वह अखिलेश को मुस्लिम तुष्टिकरण के चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी में है।

जाहिर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और आस्था अब केवल निजी भावना नहीं रह गई है, बल्कि यह रणनीति और एजेंडे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। मस्जिद से लेकर मंदिर, कांवड़ यात्रा से लेकर टोपी और पटके तक हर चीज का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। 'हरा' और 'भगवा' के बीच की यह लड़ाई अब केवल तस्वीरों और बयानों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-देहात के मतदाता तक पहुंचने लगी है। 2027 का विधानसभा चुनाव जब भी होगा, उसकी सियासी जमीन आज तैयार हो चुकी है। और यह भी तय है कि इस बार की लड़ाई महज दलों की नहीं होगी, बल्कि विचारधाराओं की, प्रतीकों की और पहचान की होगी।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण हंगामे का सच

राजनीति

अवधेश कुमार

लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण या इंटेंसिव रिवीजन का इलेक्टरल रोल जिस तरह विरोध और हंगामा का विषय बना है वह अनपेक्षित कतई नहीं है। कांग्रेस पार्टी और अनेक भाजपा विरोधी दल, एक्टिविस्ट, पत्रकार एनजीओ आदि काफी समय से चुनाव आयोग विरोधी तीखा अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी तो पुनरीक्षण आरंभ होने के पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि हेर-फेर कर भाजपा को जीताने का काम चुनाव आयोग करेगा। विरोधी बार-बार आयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाते और निराश वापस आते हैं । उच्चतम न्यायालय ने इस बार भी पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने की उनकी अपील खारिज कर दिया। हालांकि आगे वह सुनवाई के लिए सहमत हुआ है। सुनवाई के एक दिन पहले आईएनडीआईए की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की राजधानी पटना में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया गया।

वैसे इन पंक्तियों के लिखे जाने तक चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार लगभग 85 प्रतिशत पुनरीक्षण फॉर्म मतदाताओं ने जमा कर दिए । चुनाव आयोग का विज्ञापन कहता है कि गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई है और मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त, 2025 को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि किसी का नाम छूट गया तो दावा करने के लिए एक महीने का समय है। तो बिना देखे कि किसका नाम जुड़ा, नहीं जुड़ा इस तरह के विरोध का औचित्य क्या है? आयोग पर पहला आरोप है कि वह इतनी जल्दी बड़े प्रदेश के मतदाताओं की सूची कैसे बना लेगा? जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में पुनरीक्षण हुआ था तब 15 जुलाई से 14 अगस्त यानी वर्तमान के अनुसार ही 31 दिन का समय था। क्या 22- 23 वर्ष के बाद मतदाता सूची की गहनता से जांच परख नहीं होनी चाहिए? अगर चुनाव आयोग ने इसके लिए आवश्यक जनसंपर्क और आधार कार्य नहीं किया तो आलोचना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि पिछले 4 महीने में प्रत्येक विधानसभा, जिला में सर्व दलीय बैठक की गई और लगभग 5 हजार ऐसी बैठकों में 28 हजार लोगों ने भाग लिया। आयोग ने लगभग 80 हजार बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए हैं जो मतदाताओं के घर पहुंच रहे है। राजनीतिक दलों ने भी 1.54 लाख बूथ लेवल एजेंट बीएलए बनाए हैं। भारी संख्या में स्वयंसेवक भी सक्रिय हैं। कुल 16 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म प्रकाशित किए गए। एक फॉर्म रिसिप्ट के रुप में मतदाता के पास रहेगा और दूसरा बीएलओ रखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर भी फॉर्म जमा करने की व्यवस्था है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि ड्राइव बिल्कुल अव्यावहारिक है।

पहचान सुनिश्चित करने पर चुनाव आयोग के जोर का सबसे तीखा विरोध हो रहा है। जिन 11 दस्तावेजों की सूची आयोग ने रखी है उसे पढ़ने पर कठिनाई का आभास होता है। पहले कुछ तथ्य पर बात करें। 1 जनवरी, 2003 की सूची में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 96 लाख थी। वर्तमान में यह संख्या 7 करोड़ 89 लाख है। तो लगभग 2 करोड़ 93 लाख मतदाताओं को ही पहचान सुनिश्चित करनी होगी। जिन मतदाताओं के नाम 2003 में है उसके अलावा जिनका नाम आया उनको ही जन्मतिथि, जन्म स्थान आदि साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे। उनमें भी माता-पिता का नाम 2003 मतदाता सूची में है तो माता-पिता की पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। केवल 2003 वाली मतदाता सूची के उस हिस्से की कॉपी बीएलओ को देनी होगी जिसमें उनके माता-पिता का नाम लिखा है। जिनके नाम 2003 में है उन्हें केवल उसकी फोटो कॉपी बीएलओ को फॉर्म जमा करते समय देनी है जिसमें उनका नाम है।

क्या 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वाले के पास अगर जन्मतिथि तथा जन्म स्थान साबित करने के प्रमाण नहीं हो तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा? इसकी आशंका है। पर आयोग का कहना है कि दस्तावेजविहीन व्यक्ति की भारतीय पहचान को सुनिश्चित करने का काम क्षेत्र के एसडीम करेंगे और उनके कागजात का पता लगाने के लिए वालंटियर नियुक्त किए गए हैं। किसी की पहचान साबित करने का बिल्कुल दस्तावेज नहीं मिलता या उसे गली - मोहल्ले में भी कोई पहचानता नहीं है तो ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कर दें। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

सामान्य तौर पर विचार करें तो मतदान की दृष्टि से बहुत ज्यादा कागजातों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक समय कोई पहचान पत्र लेकर जाने की आवश्यकता नहीं थी और मतदान केंद्र पर केवल राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट बताते थे कि ये अमुक व्यक्ति हैं या नहीं। यह अत्यंत सरल व्यवस्था थी। लोकतंत्र मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अधिकारियों सबकी नैतिकता, ईमानदारी और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। बूथ लूट से लेकर फर्जी मतदाताओं की घटनाओं ने धीरे-धीरे पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। यह किसी के हित में नहीं किंतु वर्तमान ढांचे में इसके विकल्प की कल्पना ज्यादा चिंताजनक दिखने लगती है। बिहार में चुनाव आयोग ने यह डरावनी जानकारी दी है की पुनरीक्षण में ऐसे विदेशी नागरिक मिले जो मतदाता बन चुके हैं। उनकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी जा रही है और नागरिकता सुनिश्चित होने के बाद ही तय होगा कि वे मतदाता रहेंगे या नहीं। राजनीतिक दलों ने इस पर भी तूफान खड़ा कर दिया। क्या यह उचित है? निस्संदेह, आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवाना आसान नहीं होता। इसलिए चिंता का विषय है कि यह हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है।आधार को सबसे सुरक्षित माना गया। देश भर में फर्जी आधार कार्ड पकड़ में आ रहे हैं। अवैध अप्रवासियों घुसपैठियों तक के आधार कार्ड बने हुए हैं। बिहार के भारी मुसलमान जनसंख्या वाले चार सीमांचल जिलों में आधार कार्ड के आंकड़े हैरत में डालते हैं । बिहार में औसत आधार कार्ड आबादी के 94% है । किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है और आधार सैचुरेशन 126 प्रतिशत है, कटिहार (44%) में 123%, अररिया (43%) में 123%, और पूर्णिया (38%) में 121% आधार सैचुरेशन है। आबादी से अधिक आधार कार्ड कैसे बने हुए हैं? पिछले वर्ष अररिया में एक बंगलादेशी घुसपैठियों पकड़ा गया जिसके पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना से बना आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र था। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लड़ाई केवल असम और बंगाल में नहीं बिहार के इन सीमांचल जिलों में भी रही है

स्थानीय पुराने लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं लेकिन ज्यादातर की कई पीढ़ी हो चुकी है और उनके अलग बस्तियों में होने के कारण पहचान मुश्किल रहती है। क्या विरोधियों के दबाव में उन सबकी जांच नहीं होनी चाहिए? संविधान की धारा 326 चुनाव आयोग को भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में अंकित करने का अधिकार देता है। हालांकि नागरिकता की पहचान चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं है। इसीलिए उसने गृह मंत्रालय को मामला स्थानांतरित किया है। विरोधी चाहे इसे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को परोक्ष रूप से लागू करना माने या कुछ और किंतु भारतीय नागरिकों तक ही मतदान की व्यवस्था और पूरी मतदान प्रणाली की शुचिता तथा भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सतर्कता आवश्यक है। बावजूद मेरा मानना है कि पहचान सुनिश्चित करने के कागजात के संदर्भ में स्पष्ट राष्ट्रीय नीति हो जो विदेशियों घुसपैठियों को तो सामने ले परंतु किसी पात्र भारतीय के लिए तनाव और परेशानी का कारण न बने। आधार और राशन कार्ड पर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को विचार करने का सुझाव दिया है। इन्हें सुरक्षित बनाया जाना अति आवश्यक है। आधार के पीछे कल्पना यही थी कि इससे अनेक कार्डों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। दूसरे, स्थानीय लोग किसी के भारतीय होने की पुष्टि करते हैं तो पंचायत, प्रखंड ,अनुमंडल सबको पहचान सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने का दायित्व लेना चाहिए।

एक बार मतदाता सूची का प्रारूप आ जाने दीजिए और देखिए कि कितने लोग पात्र लोग इससे वंचित होते हैं। अगर संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जहां एक भी पात्र नागरिक सूची में स्थान पाने से वंचित नहीं हो वही एक भी अपात्र उसमें शामिल नहीं हो यह भी आयोग, राजनीतिक दलों, प्रशासन और हम सबका दायित्व है।

दोस्ताना माहौल बनाने में मदद करती है चापलूसी

व्यंग्य

मुकेश नेमा

लेखक मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

यदि अब तक अपना कोई काम करवाने के लिये आपकी किसी ने चापलूसी नहीं की है या अपने किसी काम के लिये आपने किसी की चापलूसी नहीं की है तो यकीन मानिये आप इस पुण्य भूमि मे अकारण ही जन्मे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कुछ है ही नहीं, और ना ही कुछ बनना चाहते है। सिरे से नाकारा है, यदि आप चापलूसी करने या करवाने लायक़ नहीं है तो किसी लायक़ नहीं हैं, यदि आप यह नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकता।

इसे कुछ इस तरह समझिए। जिससे भी आपका कुछ काम अटका है उसे अपनी बातों से यह भरोसा दिला देना कि वह बेहद होनहार, गुणी, खुशमिजाज, सहृदय, निष्पक्ष, सक्षम, तेजवान, असाधारण प्रशासक, ना भूतों ना भविष्यति टाईप की चीज है जो कि जाहिर है वो नहीं है, ही चापलूसी है। प्रशंसा की सौतेली अम्माँ मानकर ही चलिये इसे जो किसी भी बिगड़ैल बाप से अपनी बात मनवा सकती है। ऐसे में चापलूसी को लेकर हिचकना बेकार है। ये ब्रह्मास्त्र है। यदि आपको किसी से ऐसा उलटा सीधा काम निकलवाना है जो आपकी भलमनसाहत के कारण अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप निश्चिंत होकर इस टोटके पर अमल कर सकते हैं।

चापलूसी दरअसल एक कला है।अधिकांश भारतीय इस विधा मे जन्मजात प्रवीण होते है।अपनी गरज से, सामने बैठै दो कौड़ी के किसी आदमी को उसी के ऐसे सदुणों के बारे यकीन दिला देने को, जैसा कि वह हरगिज़ हरगिज़ नहीं है, आप कला नही कहेंगे तो और क्या कहेंगे।

भारतवर्ष की पवित्र भूमि के बाहर जन्मे मासूमों के भोले भाले मन मे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा ढीट और कठिन काम किया कैसे जाये ? तो उन भद्रजनों की शंका समाधान के लिये मै कहना चाहूँगा कि इसके लिये कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए। पहले तो खुद को ही समझा लीजिये की आप सही वक्तव्य जारी कर रहे हैं। इससे झूठ बोलते वक्त आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। जिसे आप सुना रहे है उसकी चिंता मत कीजिए। यदि वह काम करने की, करवाने की हैसियत रखता है तो उसे अब तक अपनी बेहूदी तारीफे सुनने की आदत हो ही चुकी होगी। आपके पहले भी बहुत से याचक उस पर अपना यह अभ्यास सत्र चला ही चुके होंगे। वैसे भी वे निश्चिंत रह सकते है क्योकि अपनी गलत सलत तारीफ़ सुनने से नाराज हों ऐसी आत्मायें भारत में जन्म लेना काफी टाईम पहले बंद कर चुकी हैं।

और फिर आप अकेले ही खुद को नहीं समझा रहे होंगे। जो आप जो लम्बी लम्बी छोड रहे है, उसे सुनने वाले के बारे मे भी तो सोचिए। उसे भी शुरूवाती दिनों में यह थोडा अटपटा लगता है।वह भौंचक्का होता है।समझ नही पाता कि यार यदि मे इतना अच्छा हूँ तो यह सब मुझे अब तक पता क्यों नहीं था। पर धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास भी जागता है, वह भी यह मानने लगता है कि जब इतने सारे लोग कह रहे है तो ये सही ही होगें और वो वाकई वैसा है भी जैसा उसे सुनाया बताया जा रहा है। धीरे-धीरे होता ये है कि उसके अंदर आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है तो वो कंबल ओढ़ कर सो जाती है और उसे यह पक्का भरोसा हो जाता है कि वह वाकई कल्कि अवतार जैसी ही कोई शख्सियत है, और उसका यह मान जाना भर आपका काम हो जाने की ग्यारंटी होता है।

कुछ शातिर क़िस्म के बंदे समझ भी जाते है कि सामने बैठा आदमी काम निकालने की गरज से चापलूसी कर रहा है।पर चूंकि यह विशुद्ध अहानिकारक प्रक्रिया है, इसलिये वह भी उसके मज़े लेता है, आप पर वह नाराज हो ऐसा क़तई नहीं होगा, और लाख टके की बात यह है कि अपनी झूठी सच्ची तारीफे सुनकर, कुछ ले देकर आपका काम तो उसे भी कर ही देना है।

चापलूसी को जीवन दर्शन समझिए। चापलूसी दोस्ताना माहौल बनाने में मदद करती है। ये रिश्तों को मजबूत करने की कारगर दवा है। इसे केवल झूठी बात कह कर नकार देना ठीक नही। ये सामने वाले की उन खूबियों की तारीफ है जो उसमे हैं ही नहीं या जो केवल आप देख पाए हैं। आप जब भी ऐसा करते है सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसकी कार्यक्षमता में सुधार होता है और वो सबसे पहले आपका काम करता है। यदि आप चापलूसी करना नहीं जानते तो कोई आपको क्यों तवज्जो देगा ? लोग आमतौर पर उनके ही नज़दीक आते है जो उनकी तारीफ करते हैं। और यह बात तो आप चाहते ही है कि दुनिया आपके प्यार में पड़ जाए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कटाक्ष

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

उल्लूपने में अदृश्य सींग से बनते-बिगड़ते काम

उल्लू हमेशा ही हिकारत की नजरों से देखा गया। यह और बात है कि उल्लू पर धन की देवी लक्ष्मी सवार है। कह सकते हैं कि आज माता लक्ष्मी की कृपा उल्लूओं पर ही बरस रही है। यहां उल्लू गाथा का वर्णन इसलिए भी हो रहा है कि एक घटना से है, जो संसार में पहली बार हुई। उल्लू अपने बार-बार के अपमान से व्यथित है। माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोला- माता लगता है मुझमें कोई न कोई कमी अवश्य है। इसी कमी के चलते मेरा तिरस्कार होता है। मेरी मूर्खों से तुलना की जाती है। इसलिए, अब मैं इस फितरत को तोड़ना चाहता हूं। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा-हे पक्षी श्रेष्ठ, तुम तो वैसे ही पूजनीय हो। जो मेरी आराधना करता है वह तुम्हें भी तो अर्घ्य देता है। तुम्हारा ये उल्लूपना ही मुझे भाया है। इसीलिए तुम्हें अपना वाहन बनाया है। उल्लू बोला ठीक है, लेकिन मेरे सींग नहीं है और मैं किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। उल्लू की मंशा भांप लक्ष्मी ने तथास्तु तो बोला, लेकिन साथ ही कहा कि तुम्हारे ये सींग अदृश्य रहेंगे। बिल्कुल टैक्स की तरह। हां, तुम इनका इस्तेमाल अपनी बुद्धिमत्ता (?) से कर सकते हो और हां, अब जाओ और संसार भर में भ्रमण करो।

जब से मां लक्ष्मी ने उल्लू का छुट्टा छोड़ा तब से ये धरती मूर्खों से अरे नहीं उल्लूओं से भर गई। अब वह एक दफ्तर के सामने था, जहां से कुछ आवाजें सुनाई दीं। अफसर अपने कर्मचारी को डपट रहा था कि निहायत ही उल्लू किस्म के हो। मूरख हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि फाइल पर वजन रखवाया जाता है। अरे! कोई कागज इधर-उधर हो गया तो बड़ी जलालत होगी। इतना सुनते ही उल्लू अपने अदृश्य सींग लेकर कर्मचारी के शरीर में प्रवेश कर गया। वहां से वो तुरत-फुरत बाहर निकला और आगे बढ़ा ही था कि एक घर से फिर शोर सुनाई दिया- बाप बेटे को खरी-खोटी सुना रहा था। वैसे बाप खरी-खरी अपने पास रखता है और खोटी-खोटी बेटे को देता है। बाप ने कहा-उल्लू हो क्या? तुम्हें मालूम भी है कि घर और बाहर के काम कैसे किए और कराए जाते हैं। बेटा उल्लू की संज्ञा पाकर क्षुब्द हुआ ही था कि यहां भी उल्लू उसके शरीर में घुसा और अपने सींग का प्रयोग कर तुरंत वहां से फुर्र हो गया। हालांकि उसे दिन में दिख नहीं रहा था, लेकिन वह अनुमान से ही उड़ रहा था। वह अब एक राजनैतिक सभा में पहुंचा और वहां जाकर अग्रिम पंक्ति में बैठा। यहां नजारा कुछ अलग ही था।

विभिन्न प्रदेश के उल्लू यहां विराजित थे और इनके सिर पर सींग भी स्पष्ट दिख रहे थे। तभी 'बड़े वाले' नेताजी आए और उल्लूओं की तारीफ में कहना शुरू किया। नेताजी ने कहा-तुम्हारे कारण ही हम हैं और सरकार है। तुम्हारे एक डाल से दूसरे डाल पर बैठने के नैतिक गुण के कारण ही तो हमारी जय जयकार है और लक्ष्मी हम पर प्रसन्न है। अग्रिम पंक्ति में बैठे उल्लू ने पहले अपने सींग बाहर निकाले और एक पंख बाहर निकालकर, जैसे हाथ उठाकर पूछा जाता है ठीक वैसा ही, कुछ पूछना चाहा- माई-बाप फिर उसका क्या होगा, जो अक्सर तंज मारा जाता है कि हर शाख उल्लू बैठे हैं अंजाम ए गुलिस्ता क्या होगा? नेताजी मुस्कुराए और कहा-ये आधुनिक एआई का युग है। यहां शाखाओं का क्या काम? फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगल हमने साफ करवा दिए हैं। शहरों में पेड़ विकास खा रहा है। शाख क्या खाक बचेगी? अब कोई गुलिस्ता संकट में नहीं रह सकता, क्योंकि यहां 'हम' हैं। अंजाम की चिंता मत करो। बस अपने काम पर लग जाओ।

कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता मांडू से निकलेगा

मांडू में कांग्रेस के दो दिन के 'नव संकल्प शिविर' में हुए राजनीतिक मंथन ने कांग्रेस विधायकों में जो नया जोश भरा है, जो उन्हें मिशन-2028 के लिए ऊर्जा देगा। कांग्रेस के 64 विधायकों और वरिष्ठ नेताओं में जिस तरह का उत्साह और जोश दिखाया, वो इस बात का संकेत है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की राह आसान नहीं होगी। इस शिविर के दौरान कांग्रेस ने कई ऐसे निर्णय लिए, जो जनता को कांग्रेस के निकट आने का रास्ता दिखाएंगे। साथ ही पार्टी भाजपा सरकार के फैसलों की असलियत भी दिखाएगी कि वे किस तरह जनता को भ्रमित करके अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं।

नव संकल्प शिविर

उमंग सिंघार

(नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा)

कांग्रेस का 'नव संकल्प शिविर' अपने मकसद में पूरी तरह सफल रहा। इससे यह संदेश भी गया कि कोई कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल न करे। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने यह उत्साह भी दिखाया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क और सदन दोनों जगह भाजपा को घेरेंगे। इस दो दिवसीय शिविर में 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। 'मध्यप्रदेश में बदलाव' का नारा बुलंद करते हुए नेताओं ने प्रदेश की हर विधानसभा सीट के सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का मंथन किया। वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों ने समूह बनाकर बेरोजगारी, महंगाई, किसान, ओबीसी आरक्षण, महिला सुरक्षा, जनजातीय मुद्दों, संगठन सृजन और जनगणना जैसे विषयों पर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपी। कांग्रेस के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी का संकल्प लिया। 10 विधायकों की कमेटियां गठित कर उन्हें रणनीतिक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई।

कांग्रेस ने शिविर में यह भी तय किया कि पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रामकता दर्शाएगी। शिविर के दौरान कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने विधायकों को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी और कहा कि डिजिटल मौजूदगी राजनीति में बहुत जरूरी है। हर विधायक जनता से जुड़े मुद्दों को सोशल प्लेटफॉर्म पर उठाए और भाजपा सरकार की कमजोरियों को उजागर करने में कोई कसर न छोड़े। यह भी तय किया कि पार्टी का डिजिटल सेल हर विधानसभा पर पैनी नजर रखेगा और जनता से मुद्दों को आगे बढ़ाएगा। सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार की विफलताओं, खामियों, भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा, ताकि भाजपा के झूठ को जनता तक पहुंचाया जाए।

जहां तक मेरा निष्कर्ष है कि यह दो दिन शिविर अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह नवयुग के संकल्प का आरंभ हैं। 'नव संकल्प शिविर' ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस केवल अतीत पर विचार नहीं कर रही, बल्कि भविष्य की ठोस रूपरेखा बना रही है। कांग्रेस ने मांडव की ऐतिहासिक धरती से मध्यप्रदेश की तक़दीर बदलने का संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, किसानों को आय का अधिकार, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करना, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन, दलितों-आदिवासियों और वंचित वर्गों को उनका अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। 'नव संकल्प शिविर' की सफलता से भाजपा में स्पष्ट घबराहट है। हमने मांडव में जनसंकल्प लिया, भाजपा की तरह पचमढ़ी में हनीमून नहीं मनाया। भाजपा डर रही है कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार, विफल योजनाओं और जनविरोधी फैसलों की परतें खोलेगी और हम यह ज़रूर करेंगे। लेकिन, नव संकल्प शिविर का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा और दीर्घकालिक है। यह शिविर एक वैचारिक और

सांगठनिक तैयारी है, जो भाजपा की जड़ें प्रदेश में हिला देने की क्षमता रखता है।

हमने लड़ने और जीतने का मन बनाया है। इस शिविर से विधायकों में नई ऊर्जा और स्पष्ट रणनीति उभरी है। यह कांग्रेस के वैचारिक नवचिंतन की शुरुआत है, जिसे प्रदेशभर में संवाद और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह संकल्प एक विचार था, जिसे ज़मीन पर उतारने की ताकत हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निरंतर समर्थन और आशीर्वाद से मिली। सर्वश्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और हरीश चौधरी जी का मार्गदर्शन और जीतू पटवारी जी का साथ हमारे लिए संबल बना। कांग्रेस के सभी विधायक शिविर में पूरी निष्ठा और गंभीरता से शामिल हुए। यह कोई साधारण बैठक नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साझा संकल्प था। हमें विश्वास है कि इस 'नव संकल्प शिविर' कांग्रेस को उर्जित करेगा। कांग्रेस ने मांडू में दो दिन का 'नव संकल्प शिविर' आयोजित करके यह दर्शा दिया कि उनके संगठन को कमजोर न समझा जाए और न भाजपा इस ग़लतफ़हमी में रहे कि जनता के पास उनके अलावा विकल्प नहीं है। सिंधिया विद्रोह जैसे प्रसंगों से सत्ता हथियाने के अलावा भाजपा ने चुनाव में जीत चुराई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने 'संकल्प-2028' के जरिए विधानसभा चुनाव से तीन साल पहले कमर कस ली। प्रदेश में कांग्रेस नए सिरे से मोर्चा संभालने की तैयारी में जुट गई। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर मिशन-2028 की रणनीति तैयार की गई।

इस शिविर को राहुल गांधी ने जिस ऊर्जा भाव से संबोधित किया, उससे विधायकों में नया जोश बना है। उन्होंने पार्टी की रणनीति, मूल्यों और समकालीन राजनीतिक चुनौतियों पर मार्गदर्शन दिया। दरअसल यह राजनीतिक ट्रेनिंग कैम्प नहीं था। क्योंकि, सभी विधायक नेता हैं और उन्हें राजनीतिक संघर्ष और चुनौतियों का अंदाजा है। ये अगले विधानसभा चुनाव के लिए 'मिशन 2028' की तैयारियों का अलख था। इसके जरिए न सिर्फ पार्टी मजबूत होगी, बल्कि इससे ज्यादा मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के मुद्दे उठाएगी।

शिविर के पहले दिन राहुल गांधी ने विधायकों को जिस जोश से संबोधित किया वो अलग तरह का इशारा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दो-चार उद्योगपतियों के हाथ में है, जिससे समाज का हर वर्ग परेशान है। संदेश यही है कि महंगाई बढ़ने का कारण यही वे उद्योगपति हैं जो भाजपा की गोद में बैठे हैं। अपने संबोधन के जरिए राहुल जी ने जातीय जनगणना के अपने मिशन को फिर दोहराया। साथ ही उन्होंने एक तरह से 2028 के विधानसभा चुनाव के मुद्दे ही तय कर दिए। शासकीय नौकरियों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को मौका दिए जाने की बात कही।

राहुल जी ने यह भी कहा कि भाजपा समाज में नफरत और वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के बाद देश के अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की योजना है और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव चोरी हो सकता है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भिड़कर चुनावी तैयारी करना है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ और युवा नेता सामंजस्य बनाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करें। इस तरह के आयोजनों को जारी रखते हुए सड़क पर भी आंदोलन करने की बात राहुल गांधी ने कही। उनके जोशीले संदेश का मौजूद विधायकों पर काफी असर दिखाई दिया और इसका जमीनी असर जल्दी ही दिखाई भी देगा।

इस शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि हर क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को न सिर्फ संबोधित किया, बल्कि उन्हें अगले चुनाव के लिए तैयारी का रास्ता भी दिखाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा अगला चुनाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैनेज रहेगा। इसलिए कांग्रेस को भी सोशल मीडिया को अपना सशक्त हथियार बनाना पड़ेगा। अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता और समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। उन्होंने संदेश दिया कि संगठन मेरे ही अनुसार चले, यह जिद छोड़नी पड़ेगी। भाजपा सरकार कुछ भी कहे, पर ये सब जानते हैं कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी की सबसे बड़ी देन है। इसलिए दावे से कहा जा सकता है कि मांडू में दो दिन के 'नव संकल्प शिविर' ने कांग्रेस के विधायकों में नया जोश भरा। उनकी यह ऊर्जा और उत्साह मध्यप्रदेश विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में भी दिखाई देगा। हम भाजपा सरकार की गलत नीतियों को घेरेंगे और जनता के हित में जो भी बेहतर होगा, उसे करने में पीछे नहीं हटेंगे। जीवन हो या पार्टी बदलाव जरूरी है और नव संकल्प से पार्टी में आया बदलाव नजर भी आएगा।

सैनिक शक्ति और आत्मनिर्भर राष्ट्र की पहचान

कारगिल विजय दिवस

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

26 जुलाई 1999! यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय सैन्य शौर्य का वह स्वर्णाक्षरी प्रमाण है जिसने दुर्गम पर्वतों की चोटी पर तिरंगे को फिर से लहराकर राष्ट्र को गौरवान्वित किया। कारगिल विजय दिवस केवल अतीत के बलिदानों का स्मरण नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के सैन्य संकल्प का भी उद्घोष है। आज भारत उस स्थिति में है जहाँ वह न केवल सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

कारगिल युद्ध के समय भारत की सैन्य तैयारियाँ कई मोर्चों पर कमज़ोर थीं–साजो-सामान, टोही तकनीक, और उच्च हिमालयी युद्ध कौशल की दृष्टि से। लेकिन इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेनाओं को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त किया, बल्कि रणनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी आधुनिक बनाया। आज की भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना नेटवर्क - सेंट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, और एआई-आधारित निगरानी प्रणाली से युक्त हैं।

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों से निकलकर रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत एचएएल द्वारा

तैयार किया गया तेजस लड़ाकू विमान, डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल श्रृंखला, और भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर – यह सब राष्ट्र की रक्षा स्वावलंबन की कहानी कहते हैं।

रक्षा निर्यात 2014 में जहाँ 1,500 करोड़ के आसपास था, वह आज 2025 में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

रक्षा बजट, 2024-25 में रू. 6.2 लाख करोड़ से अधिक हुआ, जो इस बात का संकेत है कि राष्ट्र अब सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

आज भारत केवल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चीन जैसे दोहरे खतरे वाले पड़ोसी से भी एक साथ निपटने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर सैनिक तैनाती, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (सड़क, हेलीपैड, सुरंगें) और एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसी तैनातियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, सक्रिय नीति पर चल रहा है।

भारत अब परंपरागत युद्ध से इतर ड्रोन युद्ध, साइबर वॉर और अंतरिक्ष डिफेंस की दिशा में भी अग्रसर है। डिफेंस स्पेस एजेंसी (डीएसए) की स्थापना कर भारत ने अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ड्रोन ऑपरेशन 'सिन्दूर' जैसी परियोजनाएँ यह दिखाती हैं कि भारत भविष्य की युद्ध-नीति में अग्रणी है।

स्वदेशी यूजीवी (अनमेंड ग्राउंड व्हीकल्स) और एआई आधारित सर्विलेंस सिस्टम्स ने सैनिकों का जोखिम घटाया है और सीमाओं की सुरक्षा पुख्ता की है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'अग्निपथ योजना' केवल सैन्य भर्ती नहीं है, बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और तकनीकी कौशल का संचार है। इसके माध्यम से एक डिजिटल युग के सैनिक तैयार हो रहे हैं, जो बायोमेट्रिक वॉर, नैनो डिफेंस और रोबोटिक सैनिकों के युग की नींव रखेंगे।

भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह क्वाड, आईओआर और ब्रिक्स डिफेंस फोरम जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर सैन्य कूटनीति का नेतृत्व कर रहा है। नेपाल, भूटान, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देशों को सैन्य प्रशिक्षण, हथियार और लॉजिस्टिक्स सहायता भारत द्वारा प्रदान की जा रही है।

कारगिल विजय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बलिदान केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा के लिए होते हैं। आज का भारत, शौर्य, रणनीति और स्वावलंबन का वह त्रिकोण है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जब विश्व भारत को देखता है, तो वह एक ऐसे राष्ट्र को देखता है जो अपने सैनिकों पर गर्व करता है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसाधनों से लैस कर उन्हें 'अजेय' बनाना चाहता है।

शालीन व्यंग्य के अग्रज लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी

स्मृति शेष

डॉ. हरीशकुमार सिंह

लेखक साहित्यकार हैं।

देश के जाने माने प्रतिष्ठित व्यंग्यकार गोपाल चतुर्वेदी का 84 वर्ष की आयु में 24 जुलाई की रात को लखनऊ में देहावसान हो गया। 15 अगस्त 1942 को जन्मे श्री गोपाल चतुर्वेदी का नाम जाना पहचाना होकर समकालीन व्यंग्य में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार का नाम जब लेना हो तो सबके सामने एक ही नाम होता है - गोपाल चतुर्वेदी। करीब बीस से अधिक प्रकाशित व्यंग्य संग्रह उनके खाते में हैं। काव्य संग्रह भी गोपाल चतुर्वेदी के आये हैं। उनके प्रसिद्ध व्यंग्य संकलनों में धाँधलेश्वर, राम झरोखे बैठ के, अफसर की मौत, सत्तापुर के नकटे, भारत और भैंस, कुर्सीपुर का कबीर, चुनिन्दा व्यंग्य, संकलित व्यंग्य, खरी खरी, जुगाडपुर के जुगाड़ू, पत्थर फेंको सुखी रहो, फ़ार्म हाउस के लोग आदि सम्मिलित रहे। गोपाल चतुर्वेदी जी को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान सहित अनेकों प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान देश-विदेश के मिले हैं। भारतीय पुलिस सेवा में चयन के बाद रेल, गृह, नागरिक उड्डयन आदि मंत्रालयों में उच्च पदों पर रहने और सेवानिवृति के बाद आज भी व्यंग्य लेखन में सक्रिय हैं। गोपाल चतुर्वेदी के व्यंग्य की सबसे बड़ी खासियत है कि वह कभी किसी ऐसे समकालीन, तात्कालिक विषय या घटना पर व्यंग्य नहीं लिखते जिसकी आयु क्षणभंगुर होकर भूलने लायक होती है। यदि कुछ व्यंग्य लिखे भी हैं तो उनके शिल्प ऐसे हैं कि व्यंग्य आज भी तरोताजा ही लगते हैं।

वर्तमान में व्यंग्य लेखन बहुतायत में हो रहा है और कई व्यंग्यकार सामने आ रहे हैं मगर वरिष्ठ व्यंग्यकारों की नजर में वे व्यंग्य के नाम पर कूड़ा करकट ही फैला रहे हैं और ऐसे में व्यंग्य के शिल्प, कथ्य, भाषा से अनजान व्यंग्यकारों की भरमार के बीच गोपाल चतुर्वेदी जी के व्यंग्य पढ़ना, रेगिस्तान में मीठे झरने के स्वाद से गुजरना जैसा लगता है। आज व्यंग्य में जितना वैविध्य है उतना पहले कभी नहीं रहा मगर अधिकांश व्यंग्यकार व्यंग्य के नाम पर धार्मिक और नैतिक प्रवचनकार की भूमिका अदा कर रहे हैं। गोपाल चतुर्वेदी व्यंग्य के सुनहरे दौर के शीर्ष व्यंग्यकार हैं और व्यंग्य क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उन्हें पढकर जाना जा सकता है। उनके व्यंग्य इस दृष्टि से मुकम्मिल व्यंग्य हैं कि वे अपने विषय में पूरा विस्तार लिए होते हैं और व्यंग्य केवल लिखने के लिए नहीं लिखते बल्कि व्यंग्य करने के लिए, व्यंग्य लिखते हैं जिसकी मार हमेशा बनी रहती है।

गोपाल चतुर्वेदी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में विभिन्न पदों और विभिन्न स्थानों पर रहते हुए अपने आसपास की शासकीय सेवा की विसंगतियों, अधिकारी और बाबुओं की कार्यप्रणाली को सूक्ष्मता से अनुभव किया है और व्यंग्य के लिए मुफीद विषयों को चुनकर श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ लिखी हैं। अंग्रेजी में स्नातकोत्तर होने के कारण आपके व्यंग्य में अंग्रेजी लेखकों और विभिन्न अंग्रेज व्यक्तित्वों के विवरण एक अलग ही रोचकता लिए होते हैं जो आपकी अध्ययनशीलता को भी प्रदर्शित करते हैं। आज व्यंग्य की सर्वाधिक जरुरत है क्योंकि बकौल गोपाल चतुर्वेदी जी आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय सियासत और वजारत,स्वतंत्रता संग्राम के बहुप्रचारित आदर्शों से कोसों दूर है और व्यंग्य ही समाज की इन विसंगतियों, विरोधाभासों और बकवासों से पाठक को परिचित करा सकता है। व्यंग्य समकालीन, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानवीय असंगतियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया है और गोपाल चतुर्वेदी ने अपने व्यंग्य लेखन से अपना सामाजिक दायित्व बखूबी अदा किया है।

देश की रग-रग में भ्रष्टाचार समाया हुआ है और लाख जतन के बाद भी ईमानदार सरकारें भी भ्रष्टाचार का बाल बांका नहीं कर सकीं हैं और यह तेजी से व्यवहार संस्कृति में परिणित हो रहा है ऐसे में गोपाल जी के व्यंग्य 'भारत में जीव्स' की ये

पंक्तियाँ सूत्र वाक्य सी लगती हैं -'इंडिया में नियम कायदे के हर ताली की एक चाबी घूस है। हर छोटे बड़े की यहाँ कीमत है।' नेताओं का नकटापन आम बात है और विवाद होने पर अपनी कही बात से पलट जाना फैशन हो गया है। मेरा कहने का यह मतलब नहीं था,मुझे गलत कोट किया गया है आदि कह कर बचना चाहते हैं। इसीलिये व्यंग्य 'आज के नेता की आदर्श बनावट' में गोपाल चतुर्वेदी लिखते हैं - 'आम आदमी के लिए नाक का महत्व है। नेता के लिए नहीं। उसके लिए पेट प्रासंगिक है।' नेता के लिए पेट प्रासंगिक है कहकर एक दो शब्दों में ही राजनेताओं के द्वारा किये जा रहे घोटालों का बखान कर दिया गया है। गोपाल जी का एक व्यंग्य है, 'दादा का अहिंसा उसूल' में 'आम आदमी को हाथ जोड़ने के लिए दिए गए हैं, नेता अभिनेता जैसों को जेब भरने के लिए और पुलिसवालों को डंडा चलाने के लिए। जो प्रभुदत्त हाथों का उचित इस्तेमाल नहीं करेगा वह ऊपरवाले की तौहीन करेगा।'

आमजन की बेबसी और भ्रष्ट व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। इसी व्यंग्य में 'हमारे मुल्क में सब सड़क पर होता है। बड़े छोटों के पारिवारिक झगडे,नेताओं की आपसी कलह, कवियों का कविता-पाठ, साधु का प्रवचन, आमजन का लघु-दीर्घ शंका समाधान सब सार्वजनिक प्रदर्शन और मनोरंजन की चीजें हैं।' देश की सड़कों पर हो रहे तमाशे को इंगित किया गया है।

साहित्य में पुरस्कारों को लेकर जोड़तोड़, राजनीति उठापटक चलती ही रहती है। इसलिए साहित्यिक पुरस्कारों की गरिमा आजकल घट रही है। गोपाल चतुर्वेदी का साहित्यिक सम्मानों और पुरस्कारों पर एक व्यंग्य है 'पेट और पुरस्कार'। पुरस्कार की आस में एक साहित्यकार की पीड़ा और बेबसी इस व्यंग्य में हैं और पुरस्कारों की राजनीति पर यह एक श्रेष्ठ व्यंग्य है जिसमे सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा। व्यंग्य की पंक्तियाँ देखिए- 'बुद्धिजीवियों की दिमागी कसरत से हम पूरी तरह भ्रमित हैं बस इतना जानते हैं कि पेट और पुरस्कार में कोई गहरा संबंध है। अगर मिला तो पेट हलके फुल्के पिराता है कि पहले क्यों नहीं मिला और यदि नहीं मिला तो असहनीय पीड़ा होती है कि क्यों नहीं मिला।'

व्यंग्य 'अपने अपने कूड़ेदान' में साफ़ सफाई के नाम पर हाथ की सफाई का चित्रण है कि सबको चंदे के धंधे से मतलब है। इसी व्यंग्य में साहित्यकार की पत्नी अपने पति की अतुकांत कविताओं को समय की बरबादी मानती है और कहती है कि 'असली घी सी कविता वह थी जिसे हारमोनियम लेकर गाया जा सके। उसके बाद से साहित्य का डालडा युग चल रहा है।' व्यंग्यकार ने यह पंक्तियाँ लिखकर कवि सम्मेलन के मंचों से लेकर साहित्यिक बिरादरी की खबर ले डाली है।

गोपाल चतुर्वेदी सरकारी सेवा में उच्च पदों पर रहे मगर जब व्यंग्य लेखन करते हैं तो व्यंग्य में स्वयं, बाबू या कर्मचारी के पात्र में हाजिर होकर संवाद करते हैं। यह उनके व्यक्तित्व की भी विशेषता है कि वे शीर्ष व्यंग्यकार होते हुए भी बातचीत में हंसमुख, सहज और सरल बने रहते हैं। व्यंग्य रचना का कथ्य और प्रभाव व्यंग्यकार को लोकप्रिय बनाता है क्योंकि ऐसी व्यंग्य रचना जो हमेशा पढ़ने पर ताजा और रुचिकर लगे व्यंग्य को सार्थकता प्रदान करती है। स्पष्ट है कि यहाँ व्यंग्य के शाश्वत होने की बात की जा रही है और गोपाल चतुर्वेदी के व्यंग्य के विषय जनजीवन और समाज से इस कदर जुड़े हैं कि पढने पर हमेशा नयेपन का आभास कराते हैं। गोपाल जी की व्यंग्य रचनाओं का परिवेश व्यापकता से भरा हुआ है और विसंगतियों पर आपके प्रहार देखते ही बनते हैं। गोपाल चतुर्वेदी के व्यंग्य लेखन की भाषा शैली सामान्य भाषा में विचारों की लयात्मकता बनाये रखती है और पाठक के दिल में उतरती है। गोपाल चतुर्वेदी की व्यंग्य भाषा में मौजूद अर्थ की परतें चीजों के आरपार देखने में समर्थ हैं। बौद्धिकता और पठनीयता से व्यंग्य समृद्ध होता है और गोपाल जी व्यंग्यों में यही बौद्धिकता दार्शनिक बनकर सामने आती है। कहा जाता है कि व्यंग्यकार अपने समय की शोषित-भ्रमित जनता के दर्द का अभीक उद्घोषक होता है और गोपाल चतुर्वेदी ने अपने व्यंग्यों में,इसी सत्य को संप्रेषित किया है। शालीनता की सीमा में रहकर व्यंग्य लेखन करना कठिन कार्य होता है और गोपाल जी इसीलिये शालीन व्यंग्य के अग्रज व्यंग्यकार हैं। वर्ष 2011 में उज्जैन में दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मेलन का विशाल आयोजन डॉ. शिव शर्मा ने श्री गोपाल चतुर्वेदी के मुख्य आतिथ्य में, गोपाल जी के उत्तर प्रदेश हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष रहते हुए करवाया था जिसकी यादें आज भी जहन में हैं। उनका निधन व्यंग्य जगत की अपूरणीय क्षति है।

निरंतर वर्षा के बाद भी क्षेत्र के 80 बांधों के पेट खाली

8 बांधों में जल आवक 10 से 15 प्रतिशत, 80 बांधों में जल भराव शून्य

बैतूल/मुलताई। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुए दो माह से अधिक गुजर गए हैं। अब तक संपूर्ण क्षेत्र में 402.80 मिमी वर्षा दर्ज की गई है किंतु इसके बावजूद क्षेत्र की अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं के पेट खाली है, जबकि पिछले वर्ष 25 जुलाई तक अधिकांश बांधों में संतोष जनक जल आवक हो गई थी। मुलताई क्षेत्र की 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 82 लघु सिंचाई परियोजना, कुल 88 सिंचाई परियोजनाओं में से 80 बांधों में जल आवक शून्य है जो की चिंता का विषय है। सिंचाई विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिन 8 बांधों में जल आवक हुई है उसमें भी जल आवक का प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस वर्ष बीते दो माह से रुक रुक के हो रही वर्षा का उल्लेखनीय एवं चिंताजनक पहलू यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक वर्षा रिकार्ड की गई है। वर्तमान समय तक इस वर्ष 2025 में मुलताई क्षेत्र में जहां 402 .80 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है वही वर्ष 2024 में जुलाई के वर्तमान समय तक 340. 80 मिलीमीटर वर्षा हुई थी किंतु पिछले वर्ष अब तक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक बांधों में जल आवक 50 प्रतिशत के लगभग थी और पारस डोह बांध में जल स्तर

मेंटेन करने हेतु गेट खोलना प्रारंभ कर दिया गया था।

हमारे सामने आ रही है पर्यावरण की अनदेखी– अधिक वर्षा के बावजूद बांधों में जल आवक की कमी के संबंध में कार्यपालन यंत्री सीएल मरकाम बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी बेरुखी अब हमारे सामने आ रही है। क्षेत्र में वर्षा तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई किंतु यह वर्षा संपूर्ण क्षेत्र में समान रूप से नहीं हो रही, बल्कि किसी क्षेत्र किसी ग्राम में कम तो कहीं ज्यादा हो रही है इसलिए बांधों में जल आवक की कमी बनी हुई है।

अब तक किस बांध में हुई कितनी जल आवक– मुलताई क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना के 6 बड़े बांध है जिसमें बुंडाला बांध मे अब तक 15.74 प्रतिशत जल आवक हुई है तो वही क्षेत्र की महत्वाकांक्षी चंदोरा सिंचाई परियोजना में 8.23 प्रतिशत जल भराव हुआ है। सोनखेड़ी बांध में 19.63 प्रतिशत जल आवक हुई है तो पारस डोह बांध में जल आवक दूसरे बांधो की तुलना में 45.69 प्रतिशत जल भराव हुआ है। बादल डोह बांध में यह जल आवक मात्र 8.98 प्रतिशत ही है और इससे भी अधिक निराशाजनक स्थिति देहगुड़ बांध की है जहां मात्र 3.71 प्रतिशत जल आवक हुई है। पंचधरा बांध में यह जल भराव का प्रतिशत 11.81 है तो बघोली में मात्र 9 प्रतिशत जल आवक हुई है ।

इनका कहना है –

क्षेत्र में हो रही वर्षा के चलते सिंचाई अमला अलर्ट पर है क्षेत्र के संपूर्ण 88 बांधो की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिंचाई विभाग ने सतत मॉनिटरिंग प्लान बनाया है। इस बांध सुरक्षा प्लान में सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बांध क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं कृषको को भी शामिल किया गया है और सभी से कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है। अधिकारी कर्मचारियों की रोस्टर प्रणाली से ड्यूटी लगाई गई है वर्षा के चलते सभी बांधों की कड़ी निगरानी की जा रही है किंतु इस वर्ष समान वर्षा न होने के कारण बांधों में जल आवक कम है।

– सीएल मरकाम, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मुलताई

भौंरा नगर में महिलाओं ने निकाली भव्य कावड़ यात्रा

बैतूल/भौंरा। सावन माह के शुभ अवसर पर गुरुवार को नगर में सैकड़ों महिलाओं द्वारा भक्ति और उत्साह से ओतप्रोत कावड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की खास बात यह रही कि पूरी यात्रा का आयोजन महिलाओं द्वारा ही किया गया, जो नगर में महिला सहभागिता और श्रद्धा का अनूठा उदाहरण बना। रामलीला चौक स्थित शंकर मंदिर

से यात्रा का शुभारंभ डीजे पर शिवभक्ति भजनों की धुनों के बीच हुआ। हाथों में कावड़ और हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंज उठा। महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। कावड़ यात्रा मां वीजासेन मंदिर नदी तट तक पहुंची, जहां सभी शिवभक्तों ने विधिपूर्वक जल भरा। इसके पश्चात यात्रा नगर के मुख्य मार्ग बजरंग मंदिर, मेन रोड, सीमेंट रोड होते हुए पुनः शंकर मंदिर पर समाप्त हुई, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रसादी वितरण किया गया। यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा सावन माह में हम सभी बहनों ने मिलकर यह कावड़ यात्रा शिव भक्ति और सामाजिक एकता के लिए आयोजित की है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। नगरवासियों ने जगह-जगह फूल वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आयोजन की भव्यता और अनुशासन ने सभी को प्रभावित किया।

हाईवे पर ट्रेवलर के आरपार हुई रेलिंग, बाल-बाल बचा ड्राइवर

रॉन्ग साइड आई बाइक को बचाने के दौरान हुआ हादसा

बैतूल। बैतूल-इंदौर फोरलेन पर एक ट्रेवलर वाहन सडक़ किनारे लगी रेलिंग में घुस गया। हादसे में रेलिंग वाहन के आगे वाले हिस्से से लेकर पीछे तक आरपार हो गई। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के खेड़ी

चौकी अंतर्गत दनोरा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक युवती काले रंग की बाइक चला रही थी और उसके पीछे एक युवक बैठा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार युवती सडक़ पर गलत दिशा में आ गई, जिससे सामने से आ रही ट्रेवलर को अचानक मोडऩा पड़ा और वाहन रेलिंग से जा टकराया। ट्रेवलर वाहन के ड्राइवर राहुल सिंह परिहार ने बताया कि यह नई गाड़ी थी, जो पीथमपुर से उड़ीसा स्थित एक शोरूम की ओर जा रही थी। वे अकेले ही वाहन चला रहे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर से बचने के लिए वाहन को किनारे मोडऩे की कोशिश की, जिससे यह हादसा हो गई। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सडक़ किनारे की रेलिंग खुली हुई थी, जो वाहन में सीधे जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के लिए लापरवाह बाइक सवारों को जिम्मेदार ठहराया और नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर खेड़ी चौकी प्रभारी राकेश सरेआम से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की कोई शिकायत अब तक थाने में दर्ज नहीं हुई है। यदि कोई शिकायत आती है तो मामले की जांच की जाएगी।

ताप्ती से जल लाकर शहर में हो रही सप्लाई कम बारिश होने से उत्पन्न हुई समस्या

माचना में पानी खत्म, दो दिन के अंतराल में जल सप्लाई

बैतूल। बारिश की लंबी खेंच के कारण माचना का पानी सूख गया। जिसका सीधा असर शहर की पेयजल सप्लाई पर पड़ रहा है। हालात यह है कि जहां एक दिन के अंतराल में पेयजल सप्लाई की जा रही थी, उसे अब दो दिन के अंतराल में कर दिया है। जिससे लोगों को बारिश में भी पेयजल संकट जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पहली बार जुलाई में अल्पवर्षा की स्थिति के चलते माचना नदी का जलस्तर घट गया है। नदी में पानी कम होने से नगरपालिका ने शहर में दो दिन के अंतराल से पेयजल सप्लाई का निर्णय लिया है। इस साल में यह दूसरी बार है, जब नगरपालिका को पेयजल सप्लाई के समय में परिवर्तन करना पड़ा है। बताया गया कि माचना डैम में पानी खत्म होने से डैम से होने वाली सप्लाई को बंद कर दिया गया है और ताप्ती से पानी लाकर शहर में सप्लाई किया जा रहा है। बता दे कि मई में भी माचना का पानी खत्म होने के बाद शहर में दो दिन के अंतराल से पेयजल सप्लाई शुरू कर दी थी। यह व्यवस्था करीब सवा माह चली थी।

जैसे-तैसे लौटी थी व्यवस्था, फिर बेपटरी– जुलाई के शुरूआत में माचना नदी में अचानक बाढ़ का पानी आने के बाद नगरपालिका ने शहर में एक दिन के अंतराल से पेयजल सप्लाई शुरू कर दी थी। जैसे-तैसे व्यवस्था पटरी पर लौट रही थी, कि बारिश पर ब्रेक लग गया। जिसकी वजह से माचना में जलस्तर कम हो गया। वहीं बारिश का सीजन शुरू होने के बाद डैम की गाद बाहर निकालने नगरपालिका ने डैम के दो गेट खोले

थे ताकि बाढ़ का पानी आए तो पूरा कचरा और गाद पानी के साथ बहकर निकल जाए। गेट खुलने से नदी में आया पानी बहकर निकल गया, लेकिन बाद में बारिश नहीं होने से पानी कम रह गया। बताया गया कि अभी माचना में पानी नहीं है और यदि जल्द ही तेज बारिश नहीं हुई तो पेयजल सप्लाई इसी तरह संचालित करनी पड़ेगी।

जुलाई में कम बारिश होने से उत्पन्न हुई समस्या– आमतौर पर जिले में जुलाई के समय अच्छी बारिश होती है। लेकिन इस बार मानसून ने दगा दे दिया। जुलाई के शुरूआत में तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन बाद में बारिश पर ब्रेक लग गया। बारिश नहीं होने से माचना नदी में पानी नहीं आ पाया, जो पानी आया था, वह भी गेट खुले होने के कारण बह गया। ऐसे में यदि जल्द ही बारिश नहीं होती है तो नगरपालिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि माचना डैम के खाली होने से नपा के सामने अभी से पेयजल सप्लाई को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। ताप्ती बैराज से ही पूरे शहर में पेयजल सप्लाई हो रहा है। जिसके कारण शहर के वार्डो में दो दिन के अंतराल में पानी दिया जा रहा है।

प्रतिदिन एक करोड़ लीटर से अधिक पानी की खपत – शहर के 33 वार्डो में करीब 13500 नल कनेक्शनधारी है। जिन्हें माचना फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाती है। नगरपालिका ने इन वार्डो में पानी सप्लाई के लिए शेड्यूल निर्धारित कर रखा है, जिसमें 16-16 वार्डो में एक-एक दिन के अंतराल से पानी दिया जाता है। प्रतिदिन एक करोड़ लीटर से अधिक पानी की खपत शहर में होती है। चूंकि माचना में पानी खत्म हो चुका हैं तो ऐसे में पूरी पानी की सप्लाई ताप्ती पर निर्भर हो गई है। ताप्ती से लगातार पानी लिए जाने के बाद भी शहर में पूर्ति कर पाना मुश्किल है। इसलिए दो दिन के अंतराल से पुनः पानी की सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है।

जिले में अभी तक 398.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज

जिले की औसत वर्षा 1083.9 मिमी है तथा जिले में अभी तक 398.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 394.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 25 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 14.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 25 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे तक तहसील बैतूल में 18.2, घोड़ाडोंगरी में 21.0, चिचोली में 5.4, शाहपुर में 16.2, मुलताई में 27.4, प्रभात पट्टन में 11.3, आमला में 30.0, भैंसदेही में 6.0, आठनेर में 5.1. तथा भीमपुर में 0.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

इनका कहना है–

जुलाई में बारिश कम होने से माचना नदी में पानी कम हो गया है। पानी की कमी को देखते हुए पुनः दो दिन के अंतराल से शहर में पेयजल सप्लाई शुरू की गई है। जब तक नदी में पर्याप्त पानी नहीं आ जाता हैं,सप्लाई दो दिन के अंतराल से जारी रहेगी।

– धीरेंद्र राठौर, जलशाखा प्रभारी, नगरपालिका बैतूल

स्वावलंबी भारत अभियान का जिला वर्ग में सफल उद्यमियों ने साझा किए अनुभव

स्वदेशी और स्वरोजगार का संकल्प लेकर 165 प्रतिभागियों ने लिया प्रशिक्षण

बैतूल। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान का एक दिवसीय जिला विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग 23 जुलाई को भारती एग्रो क्लस्टर महुपानी में सम्पन्न हुआ। इस शिविर में कुल 165 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण वर्ग में युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरित करने के साथ-साथ स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्र संयोजक सुधीर दातें, प्रांत संगठन मंत्री हेमन्त रावत, प्रांत महिला सहकार्य प्रमुख श्रीमती हेमलता कुंभारे, विभाग संयोजक योगेश मोहन सेठा, विभाग विस्तारक अरुण

मालवीय सहित अन्य गणमान्य वक्ताओं ने मार्गदर्शन दिया। जिले के सफल युवा उद्यमी हितेश ठाकरे ने अपनी 0 से 100 तक की सफलता की कहानी साझा की। उनके अनुभवों से कई युवाओं को स्वरोजगार के लिए नई प्रेरणा मिली। जिला संयोजक निलेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में उद्योग विभाग और आरएसईटीआई के माध्यम से युवाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, लोन एवं अनुदान की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची भी वितरित की गई और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में स्वदेशी आंदोलन के प्रेरणास्त्रोत महापुरुषों के जीवन पर आधारित ज्ञानवर्धक उद्बोधन भी हुए। सफल उद्यमियों को सम्मानित कर उनके अनुभव साझा कराए गए, जिससे प्रशिक्षार्थियों में आत्मविश्वास और जोश का संचार हुआ। इस वर्ग में स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के जिला युवा आयाम प्रमुख धर्मेंद्र सिंह परिहार, जिला कोष प्रमुख योगेश रोचलानी, जिला महिला सहसमन्वयक ममता मालवीय, वर्षा खाड़े, मीना बोरबन, नीलम वागद्रे, सुनिता देशमुख सहित जिला टोली सदस्य और समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम सोपई में हुआ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन

हर घर में पहुंचेगा शुद्ध जल, 162 ग्राम होंगे लाभान्वित

बैतूल/मुलताई। विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख द्वारा ग्राम पंचायत सोपई में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया । इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्षेत्र के 162 ग्राम लाभान्वित होगे और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से शासन की मंशा हर घर को नल लगाकर प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना हैं। ताकि प्रत्येक घर को शुद्ध पीने का पानी प्राप्त हो सके।इस योजना के द्वारा जल निगम संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति प्रत्येक घर तक नल के जरिए सुनिश्चित करेगा। विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा भूमि पूजन के पश्चात ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक दूरदर्शी और जनकल्याणकारी पहल है। यह परियोजना गाँव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और उनके शुद्ध पेयजल की समस्या का निराकरण कर उन्हें शुद्ध पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगी। इस योजना के द्वारा भाजपा की प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाकर परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इस अवसर भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश पाठक एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामवासी एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का जीवन चरित्र समाज के लिए प्रेरणादायक: मंत्री शाह

अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जताया आभार

बैतूल। मप्र के जनजातीय मंत्री विजय शाह शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर बैतूल पहुंचे। इस दौरान स्थानीय सर्किट हाउस पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जनजातीय मंत्री श्री शाह का पुष्प गुच्छ से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री श्री शाह को जनसंपर्क विभाग द्वारा मध्य प्रदेश संदेश वाचन की प्रति ससम्मान भेंट की गई। इस अवसर पर जनजातीय मंत्री श्री शाह ने अहिल्या बाई होल्कर को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन चरित्र पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। आधुनिक

समाज में अपने क्रियाकलापों, न्याय यवस्था से अहिल्या माता ने समाज और देश को सशक्त मार्ग दिखाया है। उनका शासन काल सुराज, स्वराज, सुशासन, सुव्यवस्था, संपन्नता, विकास और निर्माण का पर्याय था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट कर अहिल्या माता के आदर्शों, उनके चरित्रों, समाज के लिए किए गए उनके कार्यों को जनजागृति के रूप में लाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि आने वाले समय में पाठ्यपुस्तकों में शामिल किए जाने की घोषणा की है। यह कदम आने वाली पीढियों को अपने इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को जोडऩे में अहम भूमिका निभाएगा। अब आने वाली पीढ़ी भी महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ पाएगी और समाज का मार्गदर्शन करेंगी, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य मंगल सिंह धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से जनमानस को बचाने स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

बैतूल। वर्षा ऋतु में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि वर्षा ऋतु में मुख्य रूप दूषित जल के सेवन से डायरिया, पेचिश एवं हैजा, टाइफाईड पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। पेयजल के रूप में शुद्ध उबला हुआ जल का उपयोग करें। कुछ भी खाने के पहले व शौच के पश्चात साबुन से अवश्य हाथ धोएं। शुद्ध पेयजल की कमी के कारण, दूषित जल पीने से सबसे अधिक बीमारियां होती हैं, बारिश में यह समस्या बढ़ जाती है। सीएमएचओ डॉ.हुरमाड़े ने बताया कि दूषित पानी के कारण प्रायः दस्त रोग फैलता है। मुख्य रूप से बच्चों में यह अधिक गंभीर रूप धारण कर सकता है। यह रोग इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि शरीर में से पानी निकल जाने से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। दस्त रोग की रोकथाम के लिए प्रायः शुद्ध पेयजल एवं शुद्ध भोजन का उपयोग करें। सडे-गले फल एवं खाद्य पदार्थो का उपयोग न करें। खाना खाने से पहले एवं शौच के बाद साबुन से अवश्य हाथ धोए। खुले में शौच न करें एवं शौचालय का उपयोग करें। घर के आसपास साफ-सफाई रखें, दस्त लग जाने पर ओ.आर.एस. एवं जिंक सल्फेट गोली का उपयोग चिकित्सक की सलाह अनुसार करें। खाने-पीने की वस्तुओं को ढक कर रखें, मक्खियों से बचाव करें। हरी सब्जी एवं फलों को उपयोग करने के पहले साफ पानी से धोकर ही उपयोग करें।

बुखार आने पर चिकित्सक को दिखाने की सलाह

सीएमएचओ डॉ.हुरमाड़े ने बताया कि बरसात में मलेरिया/डेंगू रोग भी फैलता है जिसमें मरीज को ठण्ड लगकर बुखार आता है। प्रायः खेत, तालाब, गड्ढे, खाई, घर के आसपास रखे हुए टूटे-फूटे डब्बे, पुराने टायर, पशु के पानी पीने का हौद इत्यादि में बरसात के दिनो में जल जमा हो जाता है। इस प्रकार के भरे हुए पानी में मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं जो बाद में मच्छर बनकर रोग फैलाते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए घर के आसपास जल जमा न होने दें, रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ ऑयल डालें। कूलर, फूलदान, फ्रिज ट्रे आदि को सप्ताह में एक बार अवश्य साफ करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। कीटनाशक का छिडक़ाव करवायें, मलेरिया रोग हो जाने पर खून की जांच अवश्य कराएं एवं चिकित्सक की सलाह से पूर्ण उपचार लें।

सर्पदंश से बचाव की दी जानकारी

सीएमएचओ डॉ.हुरमाड़े ने बताया कि वर्षा ऋतु में सर्पदंश प्रकरणों की अधिक संख्या में होते हैं। बरसात में अंधेरे में नंगे पाव न घूमे, जूतों को झाड़ कर पहने, सांप दिखने पर पास न जाए, दूर से भगायें, सर्पदंश से घबराए नहीं, व्यक्ति को सुरक्षित स्थिति में लिटाकर स्थिर करें। सांप के कटे घाव पर चीरा लगाने, जोर से रगडने, मालिश करने, सफाई करने, जडीबूटी/रसायनों का उपयोग न करें, ताकि संक्रमण तथा विष अवशोषण को नियंत्रित किया जा सके। सर्पदंश के रोगी को जल्दी से जल्दी उपचार के लिए नजदीक अस्पताल पहुंचाए।

आंखें आने पर अपने हाथ एवं चेहरे को ठंडे पानी से धोएं

उन्होंने बताया कि वर्षाकाल में आंखों में संक्रमण होने के कारण आंखों में खुजली एवं आंखें लाल हो जाती हैं। इस रोग के वायरस से संक्रमित मरीज के उपयोग की गई किसी भी वस्तु जैसे, रुमाल, तौलिया, बिस्तर का उपयोग करने से दूसरों तक संक्रमण पहुंचता है। आंखे आने पर बार-बार अपने हाथ एवं चेहरे को ठंडे पानी से धोएं, परिवार के सभी सदस्य अलग-अलग तौलिये एवं रुमाल का उपयोग करें, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे स्कूल न जाने दे तथा घर पर रखें, स्वच्छ पानी का उपयोग करें, बार-बार आंखों को हाथ न लगायें, काले चश्मे का उपयोग करें, चिकित्सक को दिखाएं।

स्वस्थ प्रदेश से ही बनाएंगे समृद्ध प्रदेश : मुख्यमंत्री

सुलभ, सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर की सेवा में ही नारायण की सेवा है। प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। स्वस्थ प्रदेश के जरिए ही हम मध्यप्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सहज, सुलभ, सस्ती, तत्परतापूर्ण और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही सरकार की प्राथमिकता है। गरीब कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए हम वचनबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन मशीनों का लोकार्पण हुआ है, यह हमारे लिए सिर्फ मशीनों का नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और अपने वचनों के प्रति समर्पण भाव का भी विस्तार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध हमीदिया अस्पताल में नव स्थापित सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इन मशीनों के लोकार्पण से प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सालय को चिकित्सा जांच की अत्याधुनिक सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध हो गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। हमीदिया अस्पताल में नई एमआरआई मशीन का लोकार्पण हुआ है। यह कष्ट के समय में जीवनदान के समान है। इससे जांच में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी शासकीय अस्पतालों में आधुनिक मशीनों द्वारा मरीजों की जांच के लिए कार्य कर रही है। सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। यह नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की सजगता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मध्यप्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों के साथ अस्पताल भी शुरू किए जा रहे हैं। देश में अपनी तरह का यह पहला मॉडल है, जहां मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए इच्छुक निवेशकों/संस्थाओं को 25 एकड़ जमीन मात्र एक रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को उच्च स्तरीय जांच सुविधाओं और आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि आमजन को सस्ती, सुलभ और समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने बताया कि शासकीय गांधी चिकित्सालय महाविद्याय और हमीदिया अस्पताल अपनी वर्षों पुरानी साख और सेवाभाव के साथ अब नई तकनीकों से भी सुसज्जित हो गया है। सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की स्थापना से मरीजों को जटिल स्वास्थ्य जांचों के लिए अब कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गंभीर मरीजों के लिए सरकार ने एयर एंबुलेंस और हेली सेवा की भी शुरुआत की है, जिससे कई मरीजों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध करवाकर उनकी जीवन रक्षा संभव हो सकी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार केवल नीतियों के निर्माण से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही आता है और यह कार्य राज्य सरकार द्वारा दृढ़ संकल्प के साथ किया जा रहा है।

प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में दिनों-दिन बढ़ रही है क्षमता और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमीदिया अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन के लोकार्पण से यहां रोजाना लगभग 2 हज़ार ओपीडी (बाहरी) और 1500 आईपीडी (आंतरिक) मरीज लाभान्वित होंगे। इससे गरीब भाई-बहनों को बड़ी सुविधा मिल गई है। अब वे भी महंगे टेस्ट और उपचार करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 17 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का भूमि-पूजन सहित विक्रम उद्योगपुरी में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है। प्रदेश के 50 जिला और 3 सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन सेवाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस की 2,575 और पीजी की 1,357 सीटें शासकीय कॉलेजों में उपलब्ध हैं। प्रदेश में वर्तमान में शासकीय और निजी मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज, 308 नर्सिंग कॉलेज और 800 हेल्थ वेलनेस सेंटर संचालित हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में अब तक 4 करोड़ 37 लाख से अधिक आयुष्मान निरामयम् कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को एक घंटे के भीतर निकटतम अस्पताल पहुंचाकर उसके प्राण बचाने में योगदान देने वाले व्यक्ति को सरकार राहवीर योजना के तहत 25 हजार रुपये देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देहदान और अंगदान करने वालों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है।

इस अवसर खेल एवं युवक कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, जीएमसी डीन डॉ. कविता सिंह, सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।

पचमढ़ी में धुंध, अनूपपुर में हाईवे बंद

ग्वालियर में स्पीकर के बंगले में पानी घुसा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। नदी-नाले उफान पर हैं। डैमों में जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर में सबसे ज्यादा 3.7 इंच पानी गिरा। रायसेन में 2.4 इंच, पचमढ़ी में 1.9 इंच, सिवनी में 1.6 इंच, भोपाल, दतिया-मलाजखंड में 1.1 इंच बारिश दर्ज की गई।

ग्वालियर में शुक्रवार सुबह विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर बारिश का पानी भर गया। इस दौरान वे बंगले पर ही थे। सूचना मिलते ही 10 मिनट में नगर निगम का अमला पहुंचा और पंप की मदद से पानी निकालने का काम शुरू किया।

जबलपुर में बरगी डैम के 7 गेटों से 40,259 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैतूल के सारणी में सतपुड़ा डैम के भी 7 गेट खोले गए हैं। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में तीन दिन से कभी तेज, कभी हल्की बारिश हो रही है। बादल और धुंध के बीच मौसम में ठंडक है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ का नजारा देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं।

मध्यप्रदेश में शुक्रवार को 19 जिलों में अति भारी और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर में सुबह तेज बारिश हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सरकारी बंगले में पानी भर गया। हजीरा इलाके में पुरानी इमारत ढह गई।

जबलपुर में बरगी डैम के दो गेट और खोले गए हैं। इससे पहले 5 गेट खोले गए थे। अब कुल 7 गेटों से 40,259 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैतूल के सारणी में सतपुड़ा डैम के भी 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मुरैना जिले में पगारा डैम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 655.88 फीट तक पहुंच गया है। इसके सभी 6 ऑटोमैटिक गेट खुल गए हैं।

नर्मदापुरम के इटारसी में तवा डैम के 3 गेट सीजन में पहली बार खोले गए। तीन गेटों को 3-3 फीट खोलकर 14,514 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। इधर, सिंगरौली में तीन घंटे में 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे घरों-दुकानों में पानी भर गया। कलेक्टर ने कल सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।

पिछले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर में सबसे ज्यादा 3.7 इंच पानी गिर गया। रायसेन में 2.4 इंच, पचमढ़ी में 1.9 इंच, सिवनी में 1.6 इंच, भोपाल, दतिया-मलाजखंड में 1.1 इंच बारिश दर्ज की गई। छतरपुर के नौगांव और खजुराहो, नरसिंहपुर, गुना, बैतूल, सागर, जबलपुर, उमरिया, मंडला, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, दमोह, रतलाम, खरगोन, विदिशा, सीहोर, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, राजगढ़ समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर रहा।

विधानसभा कैम्पस में विधायकों की नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक

पहली बार जारी हुआ ऐसा आदेश, कांग्रेस ने कहा- विधायकों के मुंह नहीं सिल सकती सरकार

भोपाल (नप्र)। 28 जुलाई से शुरू हो रहे मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी मंत्रियों और विधायकों को एक पत्र भेजा है।

दर्शक दीर्घा में दो लोगों को एक घंटे तक एंट्री- मानसून सत्र के लिए विधायकों की अनुशंसा पर दर्शक दीर्घा में सीमित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए दो व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश पत्र दिया जाएगा। दर्शक दीर्घा में एक घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति होगी। विधायकों की सुविधा अनुसार अलग-अलग घंटों में दर्शक दीर्घा में प्रवेश मिलेगा।

इसमें विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) के तहत विधायकों के विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार विधायकों के मुंह नहीं सिल सकती है।

विधायकों को क्या कहा गया- विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बीते 10 जुलाई को सभी विधायकों को एक परिपत्र भेजा। इस परिपत्र में विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की है।

विधानसभा परिसर और दर्शक दीर्घा में प्रवेश पत्र सीमित संख्या में जारी किए जाएंगे। विधायकों से अनुरोध है कि अपने एक निज सहायक और वाहन चालक का नाम, वाहन नंबर के साथ प्रवेश पत्र कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

विधायक किसी को गाड़ी में बिठाकर विधानसभा न लाएं- सत्र के दौरान विधानसभा भवन में किसी गैर या बिना प्रवेश पत्र धारी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में बिठाकर या पैदल विधानसभा परिसर और सदन की लॉबी में प्रवेश न कराएं। सभी मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों के साथ ही बड़े हथियार धारी अंगरक्षकों का सत्रावधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।

विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी ने कहा- विधायक गण विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कई बार प्रदर्शन करते रहे हैं। मेरी जानकारी में पहले कभी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ, जिसमें विधानसभा परिसर में विधायकों के नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई हो।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को धमकी

कॉल करने वाला बोला- तू जल्दी मरने वाला है, तेरा घर भी तोड़ दिया जाएगा

भोपाल (नप्र)। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। 25 जुलाई को सुबह 9:10 बजे एक नंबर से कॉल आया है। फोन करने वाले शख्स ने कहा- गोविंद सिंह तू जल्दी मरने वाला है, तेरा घर भी तोड़ दिया जाएगा।

इस धमकी भरे कॉल के बाद उन्होंने डीजीपी से लिखित शिकायत की है। बताया है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह धमकी देना लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कॉलर की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। मेरे पास उत्तरप्रदेश के नंबर से कॉल आया था। कॉलर ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कहा, 'तू जल्दी मरने वाला है।' उन्होंने कहा कि कॉलर ने यह भी धमकी दी कि मेरा मकान तोड़ दिया जाएगा। फोन पर शैलेंद्र चौहान नाम और उत्तरप्रदेश का विवरण प्रदर्शित हुआ है।

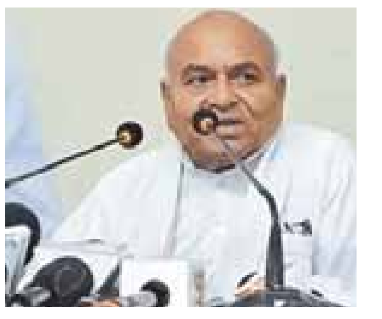

पहली बार यूथ कांग्रेस ने 15 लाख सदस्य बनाए

जिला अध्यक्ष के लिए उमंग सिंघार के जिले में सबसे ज्यादा घमासान, 15 उम्मीदवार

भोपाल (नप्र)। मप्र में युवा कांग्रेस ने सदस्य बनाने में रिकार्ड तोड़ा है। पहली बार मप्र में युवा कांग्रेस ने 15 लाख से ज्यादा बनाए हैं। बीते 20 जून से युवा कांग्रेस की सदस्यता शुरू हुई थी। 19 जुलाई को ये ऑनलाइन मेंबरशिप बंद हो गई। युवा कांग्रेस के चुनाव में सबसे ज्यादा घमासान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गृह जिले धार में देखने को मिला है। धार में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है।

कमलनाथ के जिले में मुकाबला नहीं- पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए कोई मुकाबला नजर नहीं आया। दोनों जिलों में सिर्फ एक-एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। हरदा में भी सिंगल केंडिडेट रहा। इन तीनों जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे।

दो महीने तक चलेगी स्क्रूटनी- युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए चलाए गए सदस्यता अभियान में नए मेंबर्स ने सदस्यता लेने के बाद 6 पदों के लिए मतदान किया है। ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष का वोट डाले हैं। अब दो महीनों तक सभी वोटों की स्क्रूटनी होगी। इसमें ये देखा जाएगा कि वोट देने वाले ने अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं या नहीं, मतदान के बाद वीडियो अपलोड किया है या नहीं। यदि मेंबरशिप फीस अदा नहीं की है तो वोट रिजेक्ट माना जाएगा।

भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे हमीदुल्ला, निगम अध्यक्ष ने लगाया आरोप, बोले- नवाब ने राष्ट्रभक्तों पर गोलियां चलवाईं, अब नाम बदलेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला के नाम से बने मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने को लेकर सियासत गरमा गई है। नगर निगम की बैठक में अस्पताल के साथ स्कूल और कॉलेज के नाम बदलने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने-सामने आ चुके हैं। नौबत हाथापाई तक आ गई। प्रस्ताव अब प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।

निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिख चुके हैं। साथ ही व्यक्तिगत भी मिलने वाले हैं। नाम बदलने के मुद्दे पर मीडिया ने निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी से बात की और जाना कि आखिर उन्होंने यह मांग क्यों उठाई? वहीं, अब निगम में प्रस्ताव पास होने पर आगे क्या होगा?

सूर्यवंशी बोले- पाकिस्तान का वजीर बनने का सपना था- अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा, नवाब हमीदुल्ला गद्दार थे, यह मैं ही नहीं पूरे भोपाल के देशभक्त मानते हैं। सबको पता है कि भोपाल की रियासत को नवाब हमीदुल्ला ने 2 साल तक भारत में विलय नहीं होने दिया, बल्कि वे पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते हैं। वे पाकिस्तान का वजीर बनना चाहते थे। ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि इतिहास है।

इसके लिए देशभक्तों को विलिनीकरण आंदोलन चलाना पड़ा। हमीदुल्ला ने यह नौबत पैदा कर दी थी। आंदोलन करने वाले राष्ट्रभक्तों पर नवाब ने गोलियां चलवाई। क्या ये देशभक्ति की श्रेणी में आता है? वह देश का गद्दार था। ये प्रमाण है।

कांग्रेसी साथ देते हैं, ये भी सामने आ चुका है।

जब बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भार्गव प्रस्ताव को रख रहे थे, तो कांग्रेसी पार्षदों को भारत माता की जय बोलना था लेकिन वे राष्ट्रभक्तों को गोली से भुनने और तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ थे।

अब सरकार के पाले में गेंद- निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने बताया कि निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया है, जो सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की ओके होते ही स्कूल, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास प्रस्ताव पहुंचेगा, जो इसकी आगे की प्रक्रिया करेंगे।

पत्र भी लिख चुके अध्यक्ष- निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने जून में भी सीएम को लिखे पत्र में नवाब हमीदुल्ला के नाम से भोपाल में संचालित हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदलकर राष्ट्रभक्तों के नाम से किए जाने की मांग की थी। पत्र में लिखा कि निगम को सड़कों और चौराहों के नामकरण करने का अधिकार है। इसलिए सितंबर-23 में हमीदिया रोड का नाम बदलकर गुरुनानक मार्ग कर दिया गया है।

चूंकि, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल समेत अन्य संस्थाओं के नाम परिवर्तन करने का अधिकार भोपाल निगम को नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव इन्हें बदलें। इस संबंध में जल्द ही सीएम डॉ. यादव से व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा।

अमरकंटक में देश के सभी राज्यों को मिलेगी ट्रेनिंग

केंद्र सरकार से एग्रीमेंट के बाद एक्सीलेंस सेंटर के रूप में करेगा काम

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक में अब देश के उन सभी राज्यों के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी, जहां आदिवासियों के उत्थान के लिए पेसा एक्ट लागू है। इन राज्यों में मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

एमपी में पेसा एक्ट के जरिए 8 हजार से अधिक विवादों का निराकरण चौपाल के माध्यम से किया जा चुका है और इसके लिए थाना, कचहरी के चक्कर काटने से लोगों को निजात मिली है।

जनजातीय समुदाय ने प्रदेश में अब तक लगभग 8 हजार से अधिक विवाद के प्रकरणों का चौपाल के माध्यम से निराकरण कर मिसाल पेश की है। इसमें दो भाइयों के बीच, पति-पत्नी, पिता-पुत्र सहित जमीन संबंधी विवाद शामिल हैं। जनजातीय समुदाय के लोगों को छोटे-छोटे विवाद में पुलिस थाने के चक्कर न लगाने पड़ें, वे आपस में बैठकर ही मामले सुलझाएं और उनकी परंपरा-कला- संस्कृति की भी रक्षा हो सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पेसा अधिनियम लागू किया है।

पेसा अधिनियम में मध्यप्रदेश में तीन प्रकार की समितियां काम कर रही है। इसमें शांति और विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति और वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति शामिल हैं।

शांति और विवाद निवारण समिति की संख्या 11 हजार 639 है।

वन संसाधन योजना और नियंत्रण समिति की संख्या 11 हजार 331 है। सहयोगिनी मातृ निवारण समिति की संख्या 21 हजार 887 है।

20 जिले, 88 ब्लॉक, 5133 ग्राम पंचायतों में है पेसा अधिनियम- प्रदेश के 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों के 88 विकासखंड की 5133 ग्राम पंचायतों के 11 हजार 596 ग्रामों में पेसा एक्ट लागू है।

वर्तमान में 4850 पेसा मोबलाइजर कार्य कर रहे हैं।

पेसा कानून के लागू होने के बाद राज्य में अब तक 11 हजार 538 खाते खोले गए हैं।

केंद्र के अफसरों ने की सराहना ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ

एमपी में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन की केंद्र के अफसरों ने सराहना की है। इसी के चलते पिछले दिनों पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज ने एमपी सरकार और ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बीच एग्रीमेंट के दौरान कहा कि यह त्रिपक्षीय समझौता अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए महत्पूर्ण कदम है।

विवादों का समाधान करने की जो प्रक्रिया है, उसे बाकी लोगों को भी सीखने की जरूरत है। भारद्वाज ने कहा कि पेसा कानून पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी अमरकंटक में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए जो समझौता हुआ है, उस समझौते से मध्यप्रदेश को ही नही सभी 10 पेसा राज्यों को भी फायदा होगा।

पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996) एक्ट के लिए देश में पहली बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इसके पहले राज्य स्तर पर इसकी ट्रेनिंग कराई जाती थी। जनजातीय पंचायतों में आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पेसा एक्ट लागू किया है। जनजातीय समुदाय में नेतृत्व क्षमता का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक कानूनों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। साथ ही शोध कार्य भी होगा।

विंध्य की विरासत से समृद्ध होगी
मध्यप्रदेश पर्यटन की पहचान
मध्यप्रदेश पर्यटन
क्षेत्रीय पर्यटन
कॉन्क्लेव
26-27 जुलाई, 2025 | रीवा
अद्भुत वन्यजीवन-अनोखे गंतव्य
शुभारंभ
सायं 6:00 बजे। कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम, रीवा, मध्यप्रदेश
एवं
कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम
सायं 5:00 बजे। सैनिक स्कूल परिसर, रीवा
मुख्य अतिथि
डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
पर्यटन विकास को नए आयाम
होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस और ईको-टूरिज्म क्षेत्रों में निवेश करने वाले 6 प्रमुख निवेशकों को प्रदान किए जाएंगे 'लेटर ऑफ अवॉर्ड'
पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में संचालित 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' की बुकिंग अब जुड़ेगी IRCTC पोर्टल से
ग्रामीण होम-स्टे अब मेक माय ट्रिप, यात्रा, ईज़ माय ट्रिप जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल एजेंसियों से जुड़ेंगे
2 प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों, Barcode Experiential और Qyuki Digital के साथ रणनीतिक साझेदारी हेतु एमओयू
शहडोल में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन युवाओं को मिलेंगे रोज़गार के अवसर
कला और हस्तशिल्प केंद्र स्थापित करने के लिए ग्राम सुधार समिति एमएम फाउंडेशन और समर्थ संस्था के साथ होगा अनुबंध
सीधा प्रसारण
@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhypradesh
@JansamparkMP
JansamparkMP
D-11071/25